नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. GJHIN/25/A2786

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 01
अंक : 276
दि. 09.07.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

बरुईपुर दुष्कर्म-हत्या मामले में मुख्य आरोपी एनकाउंटर में ढेर: क्राइम सीन रीक्रिएशन के दौरान पुलिस पर फायरिंग का दावा, मुठभेड़ के बाद बंगाल की राजनीति गरमाई

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित बरुईपुर दुष्कर्म एवं हत्या मामले में बुधवार तड़के उस समय बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल के मुठभेड़ में मारे जाने की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, आरोपी को अपराध स्थल पर घटनाक्रम का पुनर्निर्माण (क्राइम सीन रीक्रिएशन) कराने के लिए ले जाया गया था। इसी दौरान उसने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया, पुलिस टीम पर गोली चलाई और मौके से भागने का प्रयास किया। पुलिस का कहना है कि आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने मुठभेड़ से संबंधित वैधानिक और कानूनी प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। वहीं इस घटनाक्रम ने कानून-व्यवस्था के साथ-साथ पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी नई बहस छेड़ दी है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रभास मंडल को मंगलवार देर रात सुरक्षा घेरे में घटनास्थल पर ले जाया गया था, ताकि जांच के दौरान घटनाओं का क्रम समझा जा सके और उपलब्ध साक्ष्यों का मिलान कराया जा सके। पुलिस का दावा है कि इसी दौरान आरोपी ने अचानक एक पुलिसकर्मी का हथियार छीन लिया और पुलिस दल पर फायरिंग कर दी। इसके बाद उसने मौके से भागने का प्रयास किया। अधिकारियों के मुताबिक स्थिति को नियंत्रित करने और आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। उसे तुरंत बरुईपुर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

यह मामला पिछले सप्ताह उस समय पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया था, जब चार जुलाई को एक नाबालिग लड़की रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गई थी। परिजनों द्वारा तलाश के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल सका। अगले दिन सूरज्यापुर हाट क्षेत्र में बोरे में बंद उसका शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म और हत्या की आशंका सामने आने के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और व्यापक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया।

घटना के बाद बरुईपुर और आसपास के क्षेत्रों में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। आक्रोशित लोगों ने कई स्थानों पर सड़क जाम किया, आगजनी की और पुलिस वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल तैनात करना पड़ा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी।

इस बीच घटना के कुछ घंटों बाद भीड़ ने संदेह के आधार पर इंद्रजीत मंडल नामक एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस की प्रारंभिक जांच में उसे इस अपराध से असंबंधित और निर्दोष बताया गया। इस घटना ने भी भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेने की प्रवृत्ति पर गंभीर सवाल खड़े किए। पुलिस ने स्पष्ट किया कि निर्दोष व्यक्ति की मौत की भी अलग से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बरुईपुर दुष्कर्म एवं हत्या मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छह सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। अब तक इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियां घटनास्थल से मिले वैज्ञानिक साक्ष्यों, डिजिटल डेटा, फॉरेंसिक रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।

हालांकि मुख्य आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद राजनीतिक विवाद भी तेज हो गया है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में अब कथित तौर पर "उत्तर प्रदेश मॉडल" अपनाया जा रहा है और कानून के बजाय मुठभेड़ों की राजनीति शुरू हो गई है। उन्होंने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी की मौत से कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अब शायद सामने नहीं आ पाएंगे। उन्होंने पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता पर प्रश्न उठाते हुए स्वतंत्र जांच की मांग की। उनके बयान के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है।

दूसरी ओर पुलिस अधिकारियों ने अपने रुख का बचाव करते हुए कहा है कि पूरी कार्रवाई आत्मरक्षा की परिस्थितियों में की गई। पुलिस का कहना है कि आरोपी द्वारा हथियार छीनने और गोली चलाने के बाद तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था। अधिकारियों के अनुसार मुठभेड़ की प्रत्येक घटना की तरह इस मामले में भी निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और सभी आवश्यक दस्तावेजी तथा न्यायिक औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी।

बरुईपुर की यह घटना एक बार फिर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण, भीड़ हिंसा और पुलिस कार्रवाई को लेकर व्यापक बहस का कारण बन गई है। जहां एक ओर नाबालिग के साथ हुई कथित दरिंदगी ने पूरे राज्य को झकझोर दिया, वहीं दूसरी ओर मुख्य आरोपी की मुठभेड़ में मौत ने कानून, न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस की कार्यप्रणाली पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की निगाहें एसआईटी की जांच, मुठभेड़ से जुड़ी वैधानिक प्रक्रिया और आगे होने वाली आधिकारिक कार्रवाई पर टिकी हैं, जिससे पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।

'100% प्राकृतिक' और '100% शाकाहारी' जैसे दावों पर एफएसएसएआई की सख्ती तीन बड़ी कंपनियों को नोटिस; भ्रामक लेबलिंग पर सात दिन में मांगा जवाब

नई दिल्ली। खाद्य उत्पादों पर आकर्षक दावों के जरिए उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली कंपनियों पर अब भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। देश में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता अधिकारों को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एफएसएसएआई ने तीन प्रमुख कंपनियों—Lotte India, Ferns N Petals और Kubera Foods—को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन कंपनियों से सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। नियामक संस्था का आरोप है कि इनके कुछ खाद्य उत्पादों पर ऐसे दावे किए गए, जो वास्तविक तथ्यों से मेल नहीं खाते और उपभोक्ताओं को गुमराह कर सकते हैं। साथ ही कई उत्पादों में लेबलिंग संबंधी अनिवार्य नियमों का भी पालन नहीं किया गया।

एफएसएसएआई ने स्पष्ट किया है कि खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग पर लिखी जाने वाली प्रत्येक जानकारी वैज्ञानिक तथ्यों और निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। यदि कोई कंपनी बिना पर्याप्त आधार के "100 प्रतिशत प्राकृतिक", "100 प्रतिशत शाकाहारी", "नो प्रिजरवेटिव्स", "नो कलर्स एंड फ्लेवर्स" या "प्रीमियम" जैसे दावे करती है, तो वह उपभोक्ताओं को भ्रमित करने की श्रेणी में आ सकता है। ऐसे मामलों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। नियामक संस्था के अनुसार, पिछले कुछ समय से खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग और विज्ञापनों में बढ़ते भ्रामक दावों

को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। कई मामलों में एफएसएसएआई ने स्वतः संज्ञान भी लिया। जांच के दौरान पाया गया कि कुछ कंपनियां अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसे शब्दों और दावों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो उपभोक्ताओं को उत्पाद की वास्तविक गुणवत्ता और संरचना के बारे में गलत धारणा दे सकते हैं। एफएसएसएआई की जांच में सबसे अधिक अनियमितताएं लोट्टे इंडिया के कुछ उत्पादों में सामने आईं। संस्था के अनुसार कंपनी ने कई उत्पादों पर पुराने नाम वाले प्री-प्रिंटेड लेबल बिना पूर्व अनुमति के इस्तेमाल किए, जो नियमों के विरुद्ध है। इसके अलावा कंपनी के लोकप्रिय 'लोट्टे चॉको पाय' के कुछ पैक पर "100 प्रतिशत शाकाहारी" होने का दावा किया गया, जिसे नियामक ने भ्रामक माना है। जांच में यह भी पाया गया कि 'पीईपीईआरओ बिस्किट स्टिक्स' पर निर्धारित प्रारूप में पोषण संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई थी। वहीं 'लॉली ब्लिस लॉलीपॉप' में विटामिन स्तर से संबंधित आवश्यक मानकों का पालन नहीं मिला। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों की पैकेजिंग इस प्रकार तैयार की गई थी कि उपभोक्ताओं को उनमें वास्तविक फल होने का आभास हो, जबकि उत्पाद में फल मौजूद नहीं थे। साथ ही पैक के सामने अनिवार्य डिस्क्लेमर भी नहीं दिया गया था। एफएसएसएआई ने कहा कि खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग केवल आकर्षक दिखने के लिए नहीं होती, बल्कि उसका उद्देश्य उपभोक्ता को सही और पारदर्शी जानकारी उपलब्ध कराना भी होता है। यदि पैकेजिंग किसी उत्पाद की वास्तविक सामग्री से अलग संदेश देती है, तो यह उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना जाएगा। कुबेरा फूड्स के मामले में भी नियामक को गंभीर विसंगतियां मिलीं। कंपनी के 'सॉफ्ट एंड फ्रेश क्रीम बन पाइनएप्पल' उत्पाद के सामने वाले हिस्से पर "100 प्रतिशत प्राकृतिक", "नो प्रिजरवेटिव्स" और "नो कलर्स एंड फ्लेवर्स" जैसे दावे किए गए थे। लेकिन जब उत्पाद के विस्तृत लेबल की जांच की गई तो उसमें प्रिजर्वेटिव, सिंथेटिक रंग तथा फ्लेवरिंग पदार्थों का उल्लेख पाया गया। एफएसएसएआई का कहना है कि यदि किसी उत्पाद में ऐसे तत्व मौजूद हैं, तो उसे पूरी तरह प्राकृतिक या बिना प्रिजर्वेटिव वाला बताना नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे दावे उपभोक्ता को वास्तविक स्थिति से अलग जानकारी देते हैं और इसलिए स्वीकार्य नहीं हैं। इसी प्रकार फर्न्स एन पेटल्स के 'रोस्टेड ऑलमंड चॉकलेट' उत्पाद पर भी नियामक ने आपत्ति जताई है। जांच में पाया गया कि उत्पाद पर "प्रीमियम चॉकलेट" लिखा गया था, जबकि उसमें हाइड्रोजेनेटेड फैट का उपयोग किया गया था। एफएसएसएआई ने यह भी पाया कि उत्पाद पर अनुशंसित दैनिक पोषण मात्रा (आरडीए) तथा सामग्री संबंधी जानकारी निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं दी गई थी। संस्था का कहना है कि पोषण संबंधी जानकारी और सामग्री का स्पष्ट उल्लेख उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य है, ताकि वे स्वास्थ्य और आहार संबंधी सही निर्णय ले सकें। एफएसएसएआई ने तीनों कंपनियों को सात दिन के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। यदि प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जुर्माना, उत्पाद वापस मंगाने, लाइसेंस संबंधी कार्रवाई या अन्य वैधानिक कदम शामिल हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य उत्पादों पर किए जाने वाले दावे सीधे उपभोक्ताओं के विश्वास से जुड़े होते हैं। आज अधिकांश लोग स्वास्थ्य के प्रति पहले की तुलना में अधिक जागरूक हैं और "नेचुरल", "वेजिटेरियन", "शुगर फ्री", "ऑर्गेनिक" या "प्रिजरवेटिव फ्री" जैसे शब्दों को देखकर खरीदारी का निर्णय लेते हैं।

अमेरिका का बड़ा दावा: लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप, अदालत में पेश आरोपपत्र से बढ़ी हलचल

लॉस एंजिलिस। कनाडा में सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है। इस बार अमेरिका के न्याय विभाग ने एक बड़ा दावा करते हुए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके करीबी सहयोगी गोल्डी बराड़ पर निज्जर की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिकी अधिकारियों ने लॉस एंजिलिस की एक संघीय अदालत में पेश किए गए आरोपपत्र में कहा है कि इस हत्या के पीछे संगठित आपराधिक नेटवर्क की भूमिका रही और इसकी योजना कथित तौर पर बिश्नोई गिरोह के शीर्ष स्तर पर तैयार की गई थी। अदालत में दाखिल दस्तावेजों के सामने आने के बाद भारत, कनाडा और अमेरिका के बीच पहले से संवेदनशील बने इस मामले ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज कर दी है।

हरदीप सिंह निज्जर, जो कनाडा का नागरिक था और भारत द्वारा प्रतिबंधित घोषित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (केटीएफ) का प्रमुख माना जाता था, की 18 जून 2023 को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सर्रे शहर में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना उस समय भी अंतरराष्ट्रीय विवाद का कारण बनी थी और इसके बाद कनाडा तथा भारत के संबंधों में गंभीर तनाव देखने को मिला था। अब अमेरिका में पेश किए गए आरोपपत्र ने इस मामले को एक नया कानूनी और अंतरराष्ट्रीय आयाम दे दिया है।

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, लॉरेंस बिश्नोई ने अपने आपराधिक नेटवर्क के माध्यम से इस कथित साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई थी। आरोपपत्र में कहा गया है कि बिश्नोई लंबे समय से अपने गिरोह का संचालन विभिन्न देशों में मौजूद भरोसेमंद सहयोगियों के जरिए करता रहा है। जांच एजेंसियों का दावा है कि गिरोह का नेटवर्क भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों तक फैला हुआ है, जहां उसके सहयोगी अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं। अदालत में पेश दस्तावेजों के अनुसार, गोल्डी बराड़ को उत्तर अमेरिका में बिश्नोई गिरोह की गतिविधियों का प्रमुख संचालक बताया गया है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि बराड़ विदेश में बैठकर गिरोह के संचालन, संपर्क और कथित आपराधिक गतिविधियों का समन्वय करता रहा है। इसके अलावा आरोपपत्र में राजस्थान के रोहित गोदारा का भी उल्लेख किया गया है, जिसे यूरोप में गिरोह के नेटवर्क का संचालन करने वाला बताया गया है। पंजाब के सुखराज सिंह कंग का नाम भी इस कथित नेटवर्क में शामिल व्यक्तियों की सूची में दर्ज किया गया है।

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह मामला केवल एक हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठित आपराधिक नेटवर्क और उसकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के वित्तीय स्रोतों, संचार प्रणाली, अंतरराष्ट्रीय संपर्कों और कथित सहयोगियों की भूमिका की भी जांच कर रही हैं। अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।

हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पहले ही भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक विवाद का प्रमुख कारण बन चुकी है। कनाडा ने पहले भी इस मामले में गंभीर आरोप लगाए थे, जबकि भारत ने उन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए ठोस और सार्वजनिक साक्ष्य उपलब्ध कराने की मांग की थी। दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर राजनयिक संबंधों में तनाव देखा गया और कई स्तरों पर कूटनीतिक कदम भी उठाए गए। अब अमेरिकी न्याय विभाग की ओर से अदालत में प्रस्तुत आरोपपत्र ने इस संवेदनशील मामले को एक बार फिर वैश्विक चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी अदालत में आरोपपत्र दाखिल होना जांच प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन आरोपपत्र में लगाए गए आरोपों का अंतिम सत्यापन न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ही होगा। किसी भी आपराधिक मामले में आरोप लगाए जाना और दोष सिद्ध होना दो अलग-अलग कानूनी अवस्थाएं होती हैं। इसलिए अदालत में उपलब्ध कराए जाने वाले साक्ष्य, गवाहों के बयान और न्यायिक परीक्षण के बाद ही अंतिम निष्कर्ष सामने आएगा। इस घटनाक्रम ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध, सीमा पार सक्रिय गैंग नेटवर्क और सुरक्षा एजेंसियों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर भी नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है। अमेरिका, कनाडा और अन्य देशों की जांच एजेंसियां इस मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। आने वाले समय में अदालत की कार्यवाही, जांच में सामने आने वाले नए साक्ष्य और संबंधित देशों की आधिकारिक प्रतिक्रियाओं पर पूरे मामले की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी। फिलहाल अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों ने हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड की जांच को नया मोड़ दे दिया है। हालांकि अदालत में लगाए गए आरोप अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं और अंतिम निर्णय संबंधित न्यायालय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।

2006 में सूरत में आई बाढ़ के प्रति लापरवाही आज भी जारी है, प्रशासन के खिलाफ गंभीर सवाल उठाए गए हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। वर्ष 2006 में सूरत में हुए भीषण रेल हादसे में तत्कालीन गुजरात राज्य जल आपूर्ति मंत्री नरोत्तमभाई पटेल की आपराधिक लापरवाही और अधिकारियों की मिलीभगत के कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ और हजारों जानवरों की जान चली गई। इस हादसे में तापी नदी के किनारे बसे कई लोगों के घर, झोपड़ियां, गाय-भैंस, भेड़-बकरियों के बाड़े, जिन पर उनकी आजीविका निर्भर थी, रेल के पानी में बह गए। तापी नदी पर बने उकाई बांध का पानी किसानों के लिए कृषि के लिए उपयोगी है, लेकिन बांध में बढ़ते जल स्तर को नियंत्रित करने में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह विफल रही है। तापी नदी के ऊपरी इलाकों में जल प्रवाह बढ़ने पर जल स्तर को समय-समय पर नियंत्रित करना आवश्यक है। लेकिन सरकारी व्यवस्था, सरकारी अधिकारियों या मंत्रियों ने कभी इस दिशा में सोचा ही नहीं।

यह स्वाभाविक है कि बारिश के दौरान तापी नदी, कांकरापार नाला या अन्य नालों में पानी भर जाता है। लेकिन जब प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से लापरवाह हो और पानी के निपटान में विफल हो जाए, तो बाढ़ आ जाती है। सूरत शहर की बात करें तो, ये नाले कांकरापार नाले, मीठी नाले और कोयली नाले के आसपास से होकर गुजरते हैं। वहां से लेकर समुद्र में मिलने तक, दोनों किनारों पर स्वार्थी लोगों ने भ्रष्ट व्यवस्था के साथ मिलीभगत करके दोनों किनारों पर इतना दबाव बना रखा है कि पानी का प्रवाह रुक गया है। इस तथ्य से भलीभांति अवगत होने के बावजूद कि

सरकारी व्यवस्था, अधिकारी, नगर निगम के पदाधिकारी, सरकारी मंत्री और उच्च अधिकारी इस दिशा में कोई समयोचित और उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। परिणामस्वरूप, हर साल थोड़ी सी बारिश में भी सूरत शहर में पानी भर जाता है। सूरत नगर निगम की व्यवस्था इतनी विफल हो चुकी है कि दो से पांच इंच बारिश में भी पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। जिसके कारण स्कूल और कॉलेज बंद करने पड़ते हैं। 70 लाख से अधिक आबादी वाले सूरत शहर में जन्म और मृत्यु अनिश्चित हैं। कई जगहों पर जलभराव के कारण गर्भवती महिलाओं या अन्य मरीजों को आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस या निजी वाहन से अस्पताल ले जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि मृत्यु के समय भी श्मशान घाट या निजी वाहनों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। बार-बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होने के बावजूद, नगर निगम और सरकारी व्यवस्था नाले के पानी को अवरुद्ध करने वाले निर्माणों को हटाने में विफल रही है। सरकार और नगर निगम की लापरवाही के कारण सूरत शहर में एक भारी रेलगाड़ी आई और इस रेलगाड़ी का कोई कर्मचारी परिस्थितियों या बीमारी के कारण अपना कर्तव्य नहीं निभा सका, तो नगर निगम व्यवस्था ने उसे स्थायी रूप से बर्खास्त कर दिया। और आज उसका परिवार सड़क पर आ गया है। 2006 में आई यह रेलगाड़ी प्राकृतिक रेलगाड़ी नहीं थी, लेकिन राज्य सरकार के तत्कालीन पूर्व कैबिनेट मंत्री नरोत्तमभाई पटेल के आदेशों और तत्कालीन कलेक्टर की गलतियों और एम.एन.पी. की नाफ्टा प्रणाली के कारण सरकार ने 2006 में आई रेलगाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।

सूरत नगर निगम ने करोड़ों रुपये खर्च करके वर्षा जल निकासी नालियां बनवाई हैं। लेकिन समय-समय पर इनकी सफाई न होने के कारण जल प्रवाह रुक जाता है। वर्षा जल के उचित निकास के कारण पूरा सूरत शहर जलमग्न हो जाता है और नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सूरत नगर निगम के अधिकारियों को इस बात का स्पष्ट ज्ञान नहीं है कि वे जानबूझकर ऐसी लापरवाही बरत रहे हैं। इसी कारण वर्ष 2006 की भारी बारिश के बाद भी सरकार और नगर निगम की यह लापरवाही जारी है।

संपादकीय

बारह साला बच्ची पर हैवानियत का कहर

अब आए दिन देश के प्रिंट मीडिया से लेकर अन्य सूचना माध्यमों में यौन अपराधों की विचलित करने वाली घटनाएं सुर्खियों में रहती हैं। यौन लिप्साओं का यह विस्फोट विचलित करने वाला है। कोई निर्भया, किसी के साहस के बूते अपने साथ हुए अन्याय को उजागर कर देती है, वहीं देश की अनेक निर्भयाएं यौन हिंसा व क्रूरता के बावजूद गुमनामी के अंधेरे में त्रास झेलने को अभिशप्त हो जाती हैं। हाल की दो घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बारह वर्षीय बालिका को चार दिन बंधक बनाकर दो दर्जन लोगों द्वारा दुराचार किया गया। इस मामले में 18 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और कुछ गिरफ्तारियां बाकी हैं। दूसरी घटना पश्चिम बंगाल की है जहां बारुईपुर में एक किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। शव परीक्षण में पाया गया कि उसके सिर व निजी अंगों पर गंभीर चोटें थी। इतना ही नहीं, दुराचार के बाद उसे बोरे मे बंद करके जिंदा ही तालाब में डुबो दिया गया। दोनों ही घटनाएं विचलित करने वाली हैं, लेकिन श्रीगंगानगर की घटना हर संवेदनशील इंसान को हिला देने वाली है। जनाक्रोश के चलते प्रशासन ने न केवल 18 लोगों को गिरफ्तार किया बल्कि उन होटलों को भी ध्वस्त किया गया जहां अलग-अलग जगहों में बच्ची को बंधक बनाकर देह व्यापार कराया गया। निस्संदेह, मोबाइल के बढ़ते हस्तक्षेप से परिवार संस्था की चूलें हिली नजर आती हैं। कथित सोशल मीडिया समाज में विद्रूपताओं को जन्म दे रहा है। श्रीगंगानगर की बारह वर्षीय लड़की शहर से सौ किमी दूर अपने एक इंस्टाग्राम फ्रेंड से मिलने जाती है, जो उससे वहां दुराचार करता है। वहां से देर रात शहर लौटने पर एक रिक्शेवाले के झांसे में आकर होटल पहुंचती है और फिर उसके साथ दुराचार का अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाता है। परिजनों के लापता किशोरी के तलाश में थाने पहुंचने के बाद पुलिस हरकत में आती हैं, फिर उसे मुक्त कराया जाता है।

निस्संदेह, ये घटनाएं इंसानियत को शर्मसार करने वाली हैं। इस राक्षसी कृत्य से उद्वेलित लोग श्रीगंगानगर की सड़कों पर उतर आए। क्षुब्ध लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर कानून के रखवालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जनाक्रोश को देखते हुए 18 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह कि भारतीय समाज में हो रहे यौन लिप्साओं के विस्फोट की वजह क्या है? ये नैतिक पतन की पराकाष्ठा क्यों हो रही है? हवस के भूखे भेड़िए न उम्र देखते हैं, न किसी बेटी की बेबसी। उस किशोरी के साथ हुई बर्बरता के बारे में सोचकर भी रूह कांपती है। जो शायद ही जीवनभर इस त्रासदी से उबर पाये। कहीं न कहीं इंटरनेट व सोशल मीडिया पर यौन स्वच्छंदता की पश्चिम की आंधी हमारे समाज को पतित कर रही है। हमारे परंपरागत शुचिता के रिश्तों को तार-तार करके निरंकुश यौन व्यवहार को तार्किक बताने की साजिश रची जा रही है। हम बच्चों को रामराज के संस्कार देते हैं, जबकि समाज में दानवराज का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। बच्चों को भी त्याग-तपस्या से लालन-पालन करने वाले मां-बाप की बजाय आभासी दुनिया के छद्म मित्र रास आ रहे हैं। जिसके सम्मोहन में यह किशोरी घर से निकली और उसका पहला शिकार बनी। हवस के भेड़िये भी परिस्थितियों की मारी लड़कियों को ही अपने शिकंजे में लेते हैं। ऐसे में बेटियों को भी घर से निकलते वक्त समय की संवेदनशीलता और लोगों की विश्वसनीयता को परखना चाहिए। घर वालों से चोरी-छिपे अनजान लोगों पर यकीन करने की वजह से अकसर बेटियां अपराधियों की आसान शिकार बनती हैं। यौन अपराधों के उफान के दौर में पुलिस और स्त्री रक्षा से जुड़ी एजेंसियों को भी नये दौर की नई चुनौतियों के मुताबिक तैयार करना होगा। इसमें चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ी संस्थाओं की सजगता -सक्रियता बढ़ाने तथा पॉक्सो व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को सख्त बनाने की जरूरत है। अभिभावक व स्कूल-कालेज बच्चियों को यौन-हिंसा से बचने और आत्मरक्षा से जुड़े विषयों पर गंभीर चर्चा करें। यदि इस दिशा में गंभीर पहल नहीं हुई तो पश्चिमी देशों द्वारा भारत पर लगाए जा रहे 'रेप कैपिटल' के आरोप हकीकत समझे जाने लगेंगे।

Bihar में बदलाव की बयार, जाति-धर्म तोड़ न्याय के लिए एक हुआ समाज

> बिहार में जातिवादी राजनीति के गढ़ भोजपुर में सवर्ण युवक भरत तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ में हत्या ने अप्रत्याशित सामाजिक बदलाव को उजागर किया है। दलित और पिछड़े समुदाय भी न्याय के लिए सड़कों पर उतर आए हैं, जो राज्य में पारंपरिक जातिगत दीवारों को तोड़ते हुए एक नए सामाजिक सद्भाव का संकेत है। यह जनाक्रोश बिहार की राजनीति और सामाजिक सोच के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है।

जाति और धर्म के बिना आज राजनीति की कल्पना बेमानी है, लेकिन बिहार में जातिवाद का असर कुछ ज्यादा ही दिखता है। यहां मानस किस कदर जातिवाद के घेरे में है, इसे समझने के लिए किसी खास जाति के अपराधियों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई को देखना होगा। तब उस अपराधी के जाति विशेष द्वारा उसे बेकसूर बताने और कार्रवाई को जातिवादी बदला बताने की होड़ लग जाती है। लेकिन इसी बिहार में हाल ही में हुई एक घटना की प्रतिक्रिया में उभरा जनाक्रोश इसके ठीक उलट है। इसमें जाति और धर्म की सीमाएं टूट गई हैं। भोजपुर पुलिस के कथित एनकाउंटर में मारे गए सवर्ण युवक भरत तिवारी के इंसाफ के लिए उतरे लोगों के बीच कोई जातीय दीवार नजर नहीं आ रही। हालांकि इसे भी जातीय रंग देने की कोशिश की गई, तो उसके खिलाफ उसी दलित समाज के स्त्री और पुरूष मैदान में उतर आए, जिनकी रहनुमाई का दावा करने वाली राजनीति हस्ती ने यह रंग देने का प्रयास किया था। इससे इनकार नहीं कि भारतीय समाज में ऊंच-नीच का भाव रहा है। फिर भी समाज में सद्भाव, सहयोग और मेलजोल की गहरी परंपरा है। सामाजिक मामलों में कई बार जाति की दीवारें टूटती भी नजर आती हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव और राजनीति का मसला सामने आता है, जातीय सोच पूरी ताकत से उभर आती है। बिहार इस मामले में कुछ ज्यादा ही बदनाम है। ऐसे माहौल में अगर सवर्ण समुदाय के भरत तिवारी की पुलिस के हाथों हुई हत्या के खिलाफ सड़कों पर दलित और पिछड़े समुदाय तक के लोग उतर आएं तो मानना पड़ेगा कि पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था का जीन अब भी देश की रगों में बह रहा है। बस उसे जगाने की जरूरत है। हालांकि भरत तिवारी की कथित पुलिस मुठभेड़ को भी जातीय रंग देने की कोशिश भी हुई। हैरत की बात है कि इसके पीछे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी नजर आए। जातिवादी चश्मे से इस घटना को देखते हुए उन्होंने कह दिया कि भरत तिवारी चूंकि

ब्राह्मण था, इसीलिए सवर्ण समाज आक्रोशित है। उसकी जगह कोई दलित और पिछड़ा होता तो इस मामले को इतना तूल नहीं दिया जाता। मांझी के इस बयान ने जातिवादी खोल से बाहर निकले जनाक्रोश की आग में घी का काम किया। विरोध में भरत के गांव बिलौटी ही नहीं, आसपड़ोस के दलित और पिछड़े परिवार भी गुस्से से भर उठे। गंगा के कटान से प्रभावित ये लोग मांझी की लानत-मलामत में उतर आए। उन्होंने उलटे मांझी से ही पूछ लिया कि हमारे नेता होने के बावजूद उन्होंने उनकी हालत जानने की कोशिश क्यों नहीं की। लोगों का कहा था कि जिसके खिलाफ वे बोल रहे हैं, साधनहीन होने की बजाय वही व्यक्ति उनके साथ खड़ा रहा।

बिहार में ठीक साढ़े इक्कीस साल पहले इसी तरह जाति और धर्म का बंधन टूटा था। झारखंड के अलग होने के बाद राज्य में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा था। इसी दौरान बारह जनवरी 2005 को पटना के पटेल नगर से दिनदहाड़े पंद्रह साल के किसलय का अपहरण कर लिया गया। इस अपहरण के खिलाफ तब बिहार का पूरा समाज उतर आया था। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार में उतरे तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान तब जन-जन की जुबान पर चढ़ गया था। उन्होंने कहा था, मेरा किसलय लौटा दो। किसलय की वापसी का सवाल जाति और धर्म की सीमाओं को तोड़ समूचे बिहार की आवाज बन गया था। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के भरत तिवारी की कथित मुठभेड़ में हत्या के बाद एक बार फिर बिहार का समाज ठीक उसी तरह जाति और समुदाय के खांचों को तोड़ सत्य और न्याय के साथ खड़ा नजर आ रहा है।

भोजपुर जिले का जवानिया गांव गंगा के ठीक किनारे है। इस गांव को पिछले साल गंगा की लहरों ने तकरीबन लील लिया। कटान से प्रभावित लोगों को अपने घर-खेत गंवाना पड़ा, तब से ज्यादातर लोगों की स्थिति बदहाल है। प्रभावितों को घर के लिए जमीन और पैसे तो दिए गए, लेकिन जो जगह उन्हें मिली, वह गड्ढे वाली है। बाकी सहूलियतें भी ना के बराबर मिली हैं। इनकी बस्ती में हाल के दिनों तक पानी का चापाकल तक नहीं थे, कुछ थे भी तो उनमें पानी नहीं आ रहा था। इन्हीं बदहाल लोगों की आवाज बनकर भरत तिवारी सक्रिय थे। भरत तिवारी के न रहने के बाद बिलौटी और जवानिया के उजड़े लोगों का कहना है कि उन्हें भरत तिवारी की ही वजह से थोड़ी-बहुत सुविधाएं मिली हैं। इनके लिए वे ही प्रशासन से लड़ते रहे। कटान पीड़ित जवानिया गांव वालों का दर्द है कि उन्हें पानी से निकालकर फिर से पानी में ही बसा दिया गया है। उन्हें डर है कि फिर बारिश और बाढ़ आई तो उन्हें उजड़ना पड़ सकता है। भरत तिवारी इन्हीं मुद्दों को उठा रहे थे। भरत के गांव वालों का कहना है कि वह थोड़े तुनक मिजाज जरूर थे, लेकिन लोगों के सहयोग के लिए हमेशा तैयार रहते थे। प्रशासन के यहां कटान पीड़ितों की सुनवाई ना होने से भरत गुस्से में थे। गांव वाले मानते हैं कि प्रशासन के प्रति भरत के मन में गुस्सा था। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में एक पुलिस वाले का एनकाउंटर करने की भी बात कही थी। इसके वायरल होने के बाद पुलिस ने भरत के खिलाफ जांच शुरू की थी। गांव पहुंची पुलिस के सामने भरत के माता-पिता ने भी उन्हें डांटा था। पुलिस से भरत की नोकझोक और झूमाझटकी भी हुई थी। इसके बाद 16 जून को एक बयान में पुलिस ने उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर बताया था। लेकिन अगले ही दिन यानी सत्रह जून को पुलिस ने उन्हें घेर लिया। तब भरत के हाथ में पिस्तौल थी। उन्होंने जवानियां के गड्ढे भरने के साथ तीन मांगें रखीं थी। जब प्रशासन ने उनकी मांगें मानने का भरोसा दिया तो उन्होंने पिस्तौल फेंक कर सरेंडर कर दिया था। जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। पुलिस वहां से उन्हें ले गई और बाद में उन पर पंद्रह-बीस फायर करने का आरोप लगाते हुए उनके मुठभेड़ की बात कही थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया था, जहां सत्रह जून को उनकी मौत हो गई। लेकिन पुलिस की थ्योरी पर लोगों को भरोसा नहीं हुआ और इलाके का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि जब भरत ने पिस्तौल पुलिस को सौंप दी तो फिर वे गोली कैसे चला सकते हैं।

भरत की शव यात्रा में उमड़ी भीड़ बिहार के नए समाज का आइना कही जा सकती है। हालांकि बिहार सरकार का रवैया पारंपरिक रहा। वह प्रशासन के ही बचाव में नजर आई। लेकिन जनाक्रोश देखते हुए उसे झुकना पड़ा। भरत की हत्या की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा की अगुआई में जांच आयोग गठित किया गया है। इसी बीच आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिनमें डीएसपी और शाहपुर के थानेदार भी शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर सवर्ण के पक्ष में दलित और पिछड़ों के उतरने से जाति और धर्म के आधार पर चाल चलने वाली राजनीति को परेशानी जरूर महसूस हो रही होगी। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि समाज की सोई सकारात्मक आत्माएं ऐसे ही जागती हैं और बदलाव की बुनियाद बनती हैं। बस उसके लिए चिंगारी की जरूरत होती है। उम्मीद की जा सकती है कि भरत की हत्या के बाद उभरा जनाक्रोश प्राचीन भारतीय सामाजिक सोच को उभारने का प्रस्थान बिंदु बनेगा, जिसमें समायोजन होगा और मेलजोल भी।

प्रेरणा

विश्वास की विजयः जहां भरोसा होता है, वहां चमत्कार जन्म लेते हैं

मनुष्य के जीवन में अनेक ऐसे क्षण आते हैं जब उसके सामने परिस्थितियां इतनी कठिन हो जाती हैं कि उसे हर ओर अंधकार ही दिखाई देता है। उस समय न धन काम आता है, न शक्ति, न ही बड़े-बड़े संबंध। यदि कोई चीज उसे टूटने से बचाती है तो वह है—विश्वास। विश्वास वह प्रकाश है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। यह केवल किसी व्यक्ति या ईश्वर पर भरोसा करना नहीं है, बल्कि यह अपने उद्देश्य, अपने कर्म और अपने भविष्य के प्रति अटूट आस्था रखने का नाम है। विश्वास मनुष्य की सबसे बड़ी आंतरिक संपत्ति है। जिस व्यक्ति के भीतर विश्वास जीवित रहता है, वह असफलताओं से हारता नहीं, बल्कि उनसे सीखकर और अधिक मजबूत बनकर आगे बढ़ता है। प्रकृति भी हमें विश्वास का अद्भुत संदेश देती है। एक छोटा-सा बीज जब मिट्टी के भीतर दबाया जाता है, तब वह अंधकार, नमी और दबाव के बीच भी अपना विश्वास नहीं खोता। उसे भरोसा होता है कि एक दिन वह अंकुरित होगा, मिट्टी को चीरकर बाहर निकलेगा और विशाल वृक्ष बनेगा। यदि बीज अपने अस्तित्व पर संदेह कर ले, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य के जीवन में आने वाले संघर्ष भी उसे समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए आते हैं। जो व्यक्ति इन संघर्षों के बीच भी विश्वास बनाए रखता है, वही अंततः सफलता का स्वाद चखता है।

हमारे शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो बताते हैं कि भगवान को सबसे अधिक प्रिय अपने भक्त का अटूट विश्वास होता है। भगवान के लिए बाहरी वैभव, बड़े यज्ञ या महंगे उपहार उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, जितना कि निष्कपट मन और अडिग श्रद्धा। जब भक्त का विश्वास सच्चा होता है, तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आगे आते हैं। यही कारण है कि सनातन परंपरा में विश्वास को भक्ति का प्राण कहा गया है।

सुदामा और भगवान श्रीकृष्ण की मित्रता इसका अत्यंत सुंदर उदाहरण है। सुदामा अत्यंत निर्धन थे। उनके घर में कई दिनों तक भोजन नहीं बनता था। पत्नी के आग्रह पर वे अपने मित्र श्रीकृष्ण से मिलने द्वारका पहुंचे। उनके पास देने के लिए केवल मुट्ठीभर चिवड़ा था। उन्हें इस बात का संकोच भी था कि इतना साधारण उपहार द्वारकाधीश को कैसे दें। लेकिन उनके मन में यह पूर्ण विश्वास था कि उनका मित्र उन्हें पहचान लेगा। हुआ भी यही। श्रीकृष्ण स्वयं दौड़कर सुदामा के स्वागत के लिए आए, उन्हें गले लगाया और बड़े प्रेम से उनका लाया हुआ चिवड़ा खाया। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, फिर भी लौटकर देखा तो उनकी झोपड़ी महल में बदल चुकी थी। यह घटना बताती है कि जहां विश्वास और प्रेम होता है, वहां मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ईश्वर स्वयं भक्त की आवश्यकताओं को जान लेते हैं।

विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी संकट नहीं आएंगे। वास्तव में संकट ही विश्वास की परीक्षा लेते हैं। समुद्र में चलने वाला जहाज लहरों से नहीं डरता, क्योंकि उसे अपने निर्माण और दिशा पर विश्वास होता है। यदि वह हर लहर को देखकर घबरा जाए तो कभी किनारे तक नहीं पहुंच सकता। उसी प्रकार जीवन में आने वाली कठिनाइयां केवल हमारी परीक्षा होती हैं। जो व्यक्ति हर चुनौती के सामने विश्वास बनाए रखता है, वही अंततः विजेता बनता है। आज का युग तेज़ी से बदल रहा है। प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जीवन की गति तेज होती जा रही है और लोगों के बीच विश्वास कम होता जा रहा है। परिवारों में गलतफहमियां बढ़ रही हैं, मित्रताओं में स्वार्थ आ रहा है और समाज में संदेह का वातावरण बनता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग विश्वास करने से अधिक शंका करने लगे हैं। जबकि हर मजबूत संबंध की नींव विश्वास पर ही टिकी होती है। यदि विश्वास टूट जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी धीरे-धीरे बिखर जाता है।

एक गुरु और शिष्य का संबंध भी विश्वास पर आधारित होता है। जब शिष्य अपने गुरु के मार्गदर्शन पर विश्वास करता है, तभी वह ज्ञान प्राप्त कर पाता है। यदि वह हर बात पर संदेह करता रहे, तो उसका मन कभी स्थिर नहीं होगा। इसी प्रकार माता-पिता और संतान का संबंध भी विश्वास से मजबूत बनता है। जहां विश्वास होता है, वहां संवाद होता है, प्रेम होता है और अपनापन बना रहता है। आत्मविश्वास भी जीवन का अनिवार्य गुण है। कई बार लोग अपनी क्षमताओं से पहले ही हार मान लेते हैं। वे सोच लेते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते, इसलिए प्रयास भी अधूरे करते हैं। परिणामस्वरूप उन्हें सफलता नहीं मिलती और वे इसे भाग्य का दोष मान लेते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि सफलता सबसे पहले मन में जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास जगाता है, वही अपने सपनों को साकार करने का साहस कर पाता है।

इतिहास गवाह है कि संसार के महान व्यक्तियों ने असंभव परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उनके पास साधन कम थे, लेकिन आत्मविश्वास असीम था। लोगों ने उनका उपहास किया, उनकी आलोचना की, उन्हें असफल बताया, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य पर विश्वास बनाए रखा। अंततः वही लोग समाज के लिए प्रेरणा बन गए। यह सिद्ध करता है कि विश्वास परिस्थितियों का नहीं, मन की दृढ़ता का विषय है।

विश्वास का एक और महत्वपूर्ण पक्ष धैर्य है। आज अधिकांश लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। यदि प्रार्थना का उत्तर देर से मिले, यदि मेहनत का फल तुरंत न मिले, तो वे निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रकृति हमें धैर्य का पाठ पढ़ाती है। फल देने वाला वृक्ष बनने में वर्षों लगते हैं। नदी भी धीरे-धीरे अपना मार्ग बनाती है। सूर्योदय भी निश्चित समय पर ही होता है। इसी प्रकार ईश्वर की कृपा भी उचित समय पर ही प्राप्त होती है। इसलिए विश्वास रखने वाला व्यक्ति अधीर नहीं होता। वह जानता है कि जो होना है, वह सही समय पर अवश्य होगा।

विश्वास का अर्थ अंधी स्वीकृति नहीं है। सच्चा विश्वास विवेक के साथ चलता है। वह हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, सत्य का साथ देने का साहस देता है और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अंधविश्वास व्यक्ति को निष्क्रिय बना देता है, जबकि सच्चा विश्वास उसे कर्मयोगी बनाता है। यही कारण है कि श्रीमद्भगवद्गीता में भगवान श्रीकृष्ण ने कर्म और विश्वास दोनों को समान रूप से महत्वपूर्ण बताया है। जीवन में जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, तब यह याद रखना चाहिए कि हर रात के बाद सुबह होती है। बादल चाहे कितने भी घने क्यों न हों, सूर्य की किरणें उन्हें चीरकर निकल ही आती हैं। उसी प्रकार जीवन का कोई भी दुःख स्थायी नहीं होता। यदि हम अपने विश्वास को जीवित रखें और निरंतर सही दिशा में प्रयास करते रहें, तो सफलता अवश्य मिलती है।

महसूस होने वाला तापमान बने गर्मी का पैमाना

मानसून के आगमन से पहले के दिनों में कदम बाहर निकालते ही हवा दमघोंटू महसूस होने लगती है। हवा सिर्फ गर्म नहीं है; इसमें एक ऐसा भारीपन, सघनता और ठहराव है मानो वायुमंडल का वजन बढ़ गया हो और हमारी त्वचा को दबा रहा हो। दोपहर होते-होते, सामान्य वेदर ऐप हवा का तापमान 39 या 40 डिग्री सेल्सियस दिखा सकता है, जो देखने में शायद सहनीय लगे। लेकिन शरीर को यह तापमान 49-50 डिग्री सेल्सियस के समान महसूस होता है। यह कोई वहम नहीं; 'हीट इंडेक्स' की वह डरावनी वास्तविक तस्वीर है जो साबित करती है कि हमारे पारंपरिक मौसम वैज्ञानिक पैमाने इंसानी शरीर के जलवायु संकट को मापने में बुनियादी रूप से विफल हो रहे हैं। दशकों से, भारत में सार्वजनिक प्रशासन और आपातकालीन हीट प्रोटोकॉल केवल एक ही आंकड़े से संचालित हो रहे हैं: एक साधारण थर्मामीटर पर आंका जाने वाला 'ड्राई-बल्ब' तापमान। यदि राजस्थान के सूखे मैदानी इलाकों में पारा 45 डिग्री से. छू जाता है, तो उसे आधिकारिक तौर पर 'लू' (हीटवेव) घोषित कर दिया जाता है। लेकिन मौजूदा उमस भरी गर्मी कहीं अधिक कपटपूर्ण थर्मोडायनामिक सिद्धांत पर काम कर रही है। मानसून की देरी के कारण दक्षिण-पश्चिमी हवाएं आती हैं, तो ह्यूमिडिटी 60-70 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। मानव शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीने का वाष्पीकरण करता है। त्वचा से पसीना वाष्पीकृत होता है जो अपने साथ शरीर की आंतरिक ऊष्मा को बाहर ले जाता है। बहरहाल, जब आसपास की हवा पहले से ही नमी से पूरी तरह संतृप्त हो—एक भीगे हुए स्पंज की तरह—तो वाष्पीकरण की यह प्रक्रिया ठप हो जाती है। शरीर का आंतरिक अनुकूलन तंत्र काम करना बंद कर देता है, और उसका तापमान घातक सीमाओं की ओर बढ़ने लगता है। यह स्थिति हमें 'वेट-बल्ब तापमान' की चरम सीमा के खतरनाक रूप से करीब ले आती है जो कि मानव शरीर द्वारा झेली जा सकने वाली संयुक्त गर्मी और आर्द्रता की अंतिम सीमा है। अमेरिका के 'पेंसिल्वेनिया स्टेट हीट प्रोजेक्ट' के हालिया चिकित्सा अनुसंधान के मुताबिक, मानव शरीर मात्र 31 डिग्री सेल्सियस के वेट-बल्ब स्तर पर ही अपने आंतरिक तापमान पर नियंत्रण खोना शुरू कर देता है।

इस उमस भरे प्रहार का सबसे बड़ा खतरा है कि यह हमारी वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए संरचनात्मक रूप से अदृश्य बना रहता है। जून के अंत और अब जुलाई के शुरू में महानगरों में 'हीट इंडेक्स' 51 से 53 डिग्री पार कर गया। ड्राई-बल्ब तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) कठोर नियामक मानदंडों के कारण अक्सर आधिकारिक तौर पर हीटवेव की घोषणा नहीं कर सका। इससे श्रमिकों की परेशानी की अनदेखी हुई। 'लू' घोषित नहीं होती, इसलिए श्रम प्रवर्तन एजेंसियां निर्माण श्रमिकों, डिलीवरी ब्वॉयज और कृषि मजदूरों के लिए दोपहर के विश्राम की अवधि निर्धारित नहीं करतीं। इन कामकाजी लोगों को 50 डिग्री की दहकती भट्ठी जैसी स्थिति में खटना पड़ता है। वहीं 'हीटस्ट्रोक' के मामलों में स्वास्थ्य प्रणालियां अक्सर उमस के दौर में हताहतों की संख्या कम आंकती हैं।

यदि भारत को ऐसे युग में जीवित रहना है जहां 'महसूस होने वाला' तापमान नियमित रूप से 50 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू रहा हो, तो हमारी जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को क्रांतिकारी बदलाव से गुजरना होगा। आईएमडी और राज्य आपदा प्रबंधन अधिकारियों को सार्वजनिक स्वास्थ्य चेतावनियों, स्कूलों की छुट्टियों और श्रम नियमों के निर्धारण के कानूनी पैमाने के रूप में ड्राई-बल्ब थर्मामीटर को हटाकर आधिकारिक तौर पर 'कंपोजिट हीट रिस्क इंडेक्स' (संयुक्त ऊष्मा जोखिम सूचकांक) को लागू करना चाहिए। 65 फीसदी आर्द्रता वाले 40 डिग्री सेल्सियस के दिन को भी प्रशासनिक रूप से उतनी ही गंभीरता मिले, जितनी 47 डिग्री सेल्सियस वाले शुष्क दोपहर को।

इस दमघोंटू गर्मी के प्रति आम उपभोक्ताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया अधिक से अधिक निजी हाई-पावर स्प्लिट एसी खरीदने की होती है। लाखों निजी एसी बेहद गर्म हवा सीधे तंग सड़कों पर छोड़ते हैं, जिससे 'अर्बन हीट आइलैंड' का प्रभाव गहरा हो जाता है। यह शहरी गरीबों के लिए सार्वजनिक रास्तों को 'थर्मल डेथ ट्रैप' बना देता है जो एसी नहीं खरीद सकते। भारत को इसके वैश्विक संरचनात्मक विकल्पों की ओर देखना चाहिए, जैसे फ्रांस का भूमिगत 'क्लाइमस्पेस' नेटवर्क या गुजरात के 'गिफ्ट सिटी' में हमारा अपना स्वदेशी मॉडल। हमें कूलिंग को एक सेंट्रलाइज्ड पब्लिक यूटिलिटी के रूप में अपनाना होगा—यानी ऐसे 'डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम' जो इंसुलेटेड पाइपों के जरिए ठंडे पानी को पूरे वाणिज्यिक और आवासीय क्षेत्रों में घुमाकर ठंडा रख सकें।

भवन नियमों को शीशे और कंक्रीट के उन ढांचों से दूर हटना होगा जो विशाल ग्रीनहाउस जाल की तरह काम करते हैं। 'ऊर्जा संरक्षण भवन कोड' लागू कर इमारतों में प्रकाश परावर्तित करने वाली ठंडी छतें, क्रॉस-वेंटिलेशन के रास्ते और खोखली इंसुलेटेड ईंटों का उपयोग अनिवार्य किया जाए। यह अंदरूनी तापमान को 5 डिग्री तक कम कर सकता है, जिससे रहने के लिए एसी पर निर्भरता कम हो जाएगी।

जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन को सीधे नहीं, बल्कि विभिन्न कारकों को आपस में मिलाकर तेजी से प्रभावित कर रहा है। जब हवा का तापमान कुछ और कहे और इंसान की त्वचा कुछ और महसूस करे, तो हमारी सार्वजनिक नीतियों को हमेशा इंसान की त्वचा का साथ देना होगा। यह समय साधारण थर्मामीटर को विदा करने और एक ऐसा प्रशासनिक ढांचा तैयार करने का है जो हवा के इस भारी और वास्तविक संकट का दृढ़ता से मुकाबला कर सके।

अभियान

84 महादेव परिक्रमा: उज्जैन की वह दिव्य यात्रा, जो शिवभक्ति को पूर्णता तक पहुंचाती है

भारत की आध्यात्मिक परंपरा में कुछ तीर्थ ऐसे हैं, जहां केवल दर्शन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण यात्रा आत्मा को नई ऊर्जा से भर देती है। मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन ऐसा ही एक तीर्थ है, जिसे भगवान महाकाल की नगरी के रूप में विश्वभर में सम्मान प्राप्त है। यहां स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए यहां पहुंचते हैं। अधिकांश लोग महाकाल मंदिर, काल भैरव, हरसिद्धि माता और चिंतामण गणेश के दर्शन कर अपनी यात्रा पूरी मान लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उज्जैन की आध्यात्मिक पहचान केवल महाकालेश्वर तक सीमित नहीं है। इस पवित्र नगरी की धरती पर भगवान शिव के 84 प्राचीन स्वरूप विराजमान हैं, जिनकी परिक्रमा को "84 महादेव यात्रा" कहा जाता है। मान्यता है कि उज्जैन की यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती, जब तक श्रद्धालु इन 84 शिवलिंगों का दर्शन और पूजन नहीं कर लेते।

84 महादेव यात्रा केवल मंदिरों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह शिवभक्ति, तपस्या, आस्था और भारतीय संस्कृति की हजारों वर्षों पुरानी परंपरा का जीवंत स्वरूप है। स्कंद पुराण के अवंति खंड सहित अनेक धार्मिक ग्रंथों में उज्जयिनी को भगवान शिव की प्रिय नगरी बताया गया है। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने इस भूमि को अपना निवास बनाया और यहां अनेक स्वरूपों में प्रकट होकर भक्तों का कल्याण किया। समय के साथ इन स्वरूपों के स्थान पर मंदिर स्थापित हुए और आज ये सभी मिलकर 84 महादेव परिक्रमा का आधार बनते हैं।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति पाने का प्रतीक भी यह यात्रा मानी जाती है। जिस प्रकार जीवात्मा अनगिनत जन्मों की यात्रा के बाद मोक्ष की ओर बढ़ती है, उसी प्रकार 84 महादेवों की परिक्रमा मनुष्य को आत्मशुद्धि, पुण्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रदान करती है। यही कारण है कि देशभर से श्रद्धालु विशेष रूप से सावन, महाशिवरात्रि, श्रावण सोमवार और कार्तिक मास में इस यात्रा के लिए उज्जैन पहुंचते हैं।

84 महादेवों में प्रत्येक मंदिर का अपना अलग धार्मिक महत्व है। यात्रा की शुरुआत सामान्यतः अगस्तेश्वर महादेव से मानी जाती है। इसके बाद श्रद्धालु क्रमशः गुहेश्वर महादेव, डमरुकेश्वर महादेव, ढुंढेश्वर महादेव, स्वर्णजालेश्वर महादेव, त्रिविष्टपेश्वर महादेव, धारकेश्वर महादेव, दशमुखेश्वर महादेव, करभेश्वर महादेव, कंटकेश्वर महादेव, कंडुकेश्वर महादेव, सिंहेश्वर महादेव, प्रहादकेश्वर महादेव, राजेंद्रेश्वर महादेव, कोटिश्वर महादेव, विमलेश्वर महादेव, अंधकेश्वर महादेव, नीलकंठेश्वर महादेव, कपालमोचन महादेव, अनादि सिद्धेश्वर महादेव, अनादि कल्पेश्वर महादेव, शुक्रेश्वर महादेव, संगमेश्वर महादेव, हाटकेश्वर महादेव, मुकुटेश्वर महादेव, जटेश्वर महादेव, च्यवनेश्वर महादेव, अप्सरेश्वर महादेव, वरुणेश्वर महादेव, दशपुरेश्वर महादेव, नागचंद्रेश्वर महादेव, कुटुम्बेश्वर महादेव, महाकालेश्वर महादेव, जटाश्रृंगेश्वर महादेव, कर्कटेश्वर महादेव, घटकेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव, कलकलेश्वर महादेव, अर्धनारीश्वर महादेव, सौरीश्वर महादेव, कुबेरेश्वर महादेव और कुंटेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं।

इसके आगे यात्रा लोकेश्वर महादेव, तिलभांडेश्वर महादेव, गर्गेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, नुकुलेश्वर महादेव, विश्वेश्वर महादेव, चंद्रेश्वर महादेव, यमेश्वर महादेव, इंद्रेश्वर महादेव, सागरेश्वर महादेव, प्रयागेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव, गंगाधरेश्वर महादेव, वीरेश्वर महादेव, कुरुक्षेत्रेश्वर महादेव, नारदेश्वर महादेव, मातृकेश्वर महादेव, रुद्रेश्वर महादेव, दशरथेश्वर महादेव, रामेश्वर महादेव (द्वितीय), पवनकेश्वर महादेव, लकुलीश्वर महादेव, दुर्वासेश्वर महादेव, पिंगलेश्वर महादेव, कायावरोहणेश्वर महादेव, चिंतामणेश्वर महादेव, अर्केश्वर महादेव, विष्णुकेश्वर महादेव, आंगारकेश्वर महादेव, कुटिकेश्वर महादेव, समीश्वर महादेव, कपिलासंगमेश्वर महादेव, अमृतेश्वर महादेव, कर्णेश्वर महादेव, ऋणमुक्तेश्वर महादेव, स्थावरेश्वर महादेव, ब्रह्मेश्वर महादेव, जलेश्वर महादेव, आनंदेश्वर महादेव, कंठेश्वर महादेव और अंत में लोमशेश्वर महादेव के दर्शन के साथ पूर्ण होती है। इन सभी मंदिरों का महत्व केवल उनके नाम तक सीमित नहीं है। प्रत्येक शिवलिंग किसी न किसी ऋषि, देवता, ऐतिहासिक घटना या आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। उदाहरण के लिए ऋणमुक्तेश्वर महादेव को आर्थिक संकट और कर्ज से मुक्ति की कामना के लिए विशेष रूप से पूजनीय माना जाता है। नागचंद्रेश्वर महादेव का मंदिर अपनी अनूठी परंपरा के कारण प्रसिद्ध है, जहां वर्ष में केवल नागपंचमी के दिन ही गर्भगृह के दर्शन होते हैं। अर्धनारीश्वर महादेव शिव और शक्ति की एकता का संदेश देते हैं, जबकि कपालमोचन महादेव पापों से मुक्ति की आस्था का केंद्र माने जाते हैं। महाकालेश्वर स्वयं काल के स्वामी हैं, इसलिए यहां दर्शन करने से मृत्यु का भय दूर होने की मान्यता है।

84 महादेव यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि अनुशासन, धैर्य और समर्पण की साधना भी है। श्रद्धालु प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में यात्रा आरंभ करते हैं और दिनभर विभिन्न मंदिरों में जलाभिषेक, बेलपत्र अर्पित कर "ॐ नमः शिवाय" का जाप करते हुए आगे बढ़ते हैं। कई श्रद्धालु पूरी यात्रा नंगे पैर करते हैं, जबकि कुछ लोग उपवास रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान भक्तों के मन में केवल एक ही भावना रहती है—भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना।

यदि कोई श्रद्धालु पहली बार यह यात्रा कर रहा है, तो उसके लिए स्थानीय प्रशासन और धार्मिक संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले रूट मैप अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं। इस मानचित्र में सभी मंदिरों का क्रम, दूरी और पहुंचने का मार्ग स्पष्ट रूप से अंकित रहता है। अधिकांश मंदिर उज्जैन शहर के भीतर स्थित हैं, जबकि कुछ मंदिर शहर की सीमा से लगे क्षेत्रों में हैं। इस कारण यात्रा को व्यवस्थित रूप से पूरा करने के लिए रूट मैप का पालन करना सबसे उपयुक्त माना जाता है।

सामान्यतः 84 महादेव यात्रा को पूर्ण करने में दो से तीन दिन का समय लगता है। हालांकि कुछ श्रद्धालु निजी वाहन की सहायता से इसे कम समय में भी पूरा कर लेते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से बिना जल्दबाजी के प्रत्येक मंदिर में रुककर श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना करना अधिक फलदायी माना जाता है। यदि कोई भक्त प्रत्येक स्थल का महत्व समझते हुए यात्रा करे, तो यह केवल तीर्थयात्रा नहीं बल्कि आध्यात्मिक अध्ययन का अनुभव भी बन जाती है।

सावन के महीने में इस यात्रा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस दौरान पूरे उज्जैन में शिवभक्ति का अद्भुत वातावरण दिखाई देता है। मंदिरों में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय जाप, भजन-कीर्तन और विशेष पूजन आयोजित किए जाते हैं। महाशिवरात्रि पर भी हजारों श्रद्धालु 84 महादेव यात्रा का संकल्प लेकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अनेक साधु-संत भी इस अवधि में पूरी परिक्रमा कर भक्तों को धर्म और अध्यात्म का संदेश देते हैं।

यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मंदिरों की पवित्रता बनाए रखना, प्लास्टिक का उपयोग न करना, स्थानीय परंपराओं का सम्मान करना, कतारबद्ध होकर दर्शन करना और प्रशासन के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। साथ ही पर्याप्त पानी, हल्का भोजन और आरामदायक वस्त्र रखने से यात्रा अधिक सहज बन जाती है। बरसात के मौसम में फिसलन वाले स्थानों पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

आज के आधुनिक दौर में जब लोग तीर्थयात्रा को केवल पर्यटन का माध्यम मानने लगे हैं, तब 84 महादेव यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि तीर्थ का वास्तविक उद्देश्य केवल मंदिर देखना नहीं, बल्कि अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, लोभ और नकारात्मकता को पीछे छोड़कर आध्यात्मिक रूप से स्वयं को परिष्कृत करना है। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों की सच्ची भावना को सबसे अधिक महत्व देते हैं। उन्हें महंगे चढ़ावे की नहीं, बल्कि निर्मल मन, सच्ची श्रद्धा और निष्काम भक्ति की आवश्यकता होती है।

उज्जैन की 84 महादेव यात्रा इसी भावना का प्रतीक है। यह यात्रा श्रद्धालु को बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा मार्ग बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की यात्रा है।

PRGI NO. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के करकमलों से गुजरात पुलिस बल में नवनियुक्त 449 अशस्त्र सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की विशेष उपस्थिति

▸▸ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का गुजरात पुलिस बल में नए शामिल हो रहे अशस्त्र पीएसआई युवाओं से आह्वान

▸▸ निष्ठा, प्रामाणिकता एवं समाज सेवा की भावना से कर्तव्यरत रहकर 'नागरिक देवो भव' तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के मंत्र को साकार करें

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

▸▸ देश के रोल मॉडल तथा व्यापार-उद्योग क्षेत्र में वैश्विक निवेश से विकास की जो ख्याति गुजरात ने बनाई है, उसमें शांति और सुरक्षा के प्रहरी गुजरात पुलिस बल का महत्वपूर्ण योगदान है

▸▸ निष्ठा और प्रामाणिकता से कार्य करने वालों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रहती है

▸▸ आइए, हम सभी मिलकर गुजरात को शांति एवं सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक सशक्त एवं गौरवशाली बनाएं

▸▸ विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात की यात्रा में ये नवनियुक्त युवा अपने लंबे सेवा-काल के दौरान वर्ष 2047 के विकसित भारत-विकसित गुजरात के निर्माण के वाहक बनेंगे

उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

▸▸ वर्ष 2033 तक पुलिस विभाग में 50 हजार नई भर्तियां की जाएंगी

▸▸ पिछले पांच वर्षों में गुजरात पुलिस ने कुल 15,653 महिला कर्मियों की भर्ती कर महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है

▸▸ सामान्य जनता के लिए पुलिस का अर्थ अपराधियों को कानून के दायरे में लाने वाली एक फोर्स है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब भी राज्य में कोरोना महामारी, भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाएं अथवा कोई भी कठिन परिस्थिति आती है, तब जनता की सुरक्षा के लिए सबसे पहले पुलिस ही आगे आती है

▸▸ अब गुजरात के सभी जिला पुलिस मुख्यालयों के मैदान प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खोल दिए गए हैं

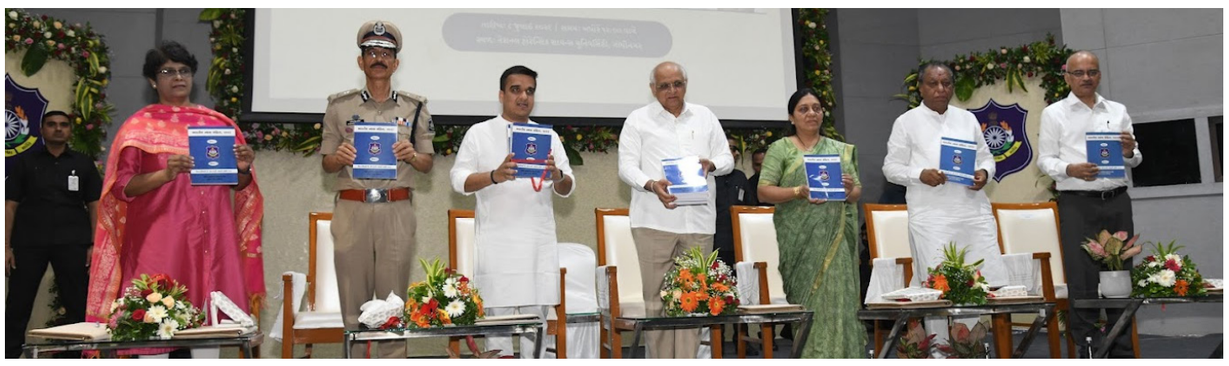

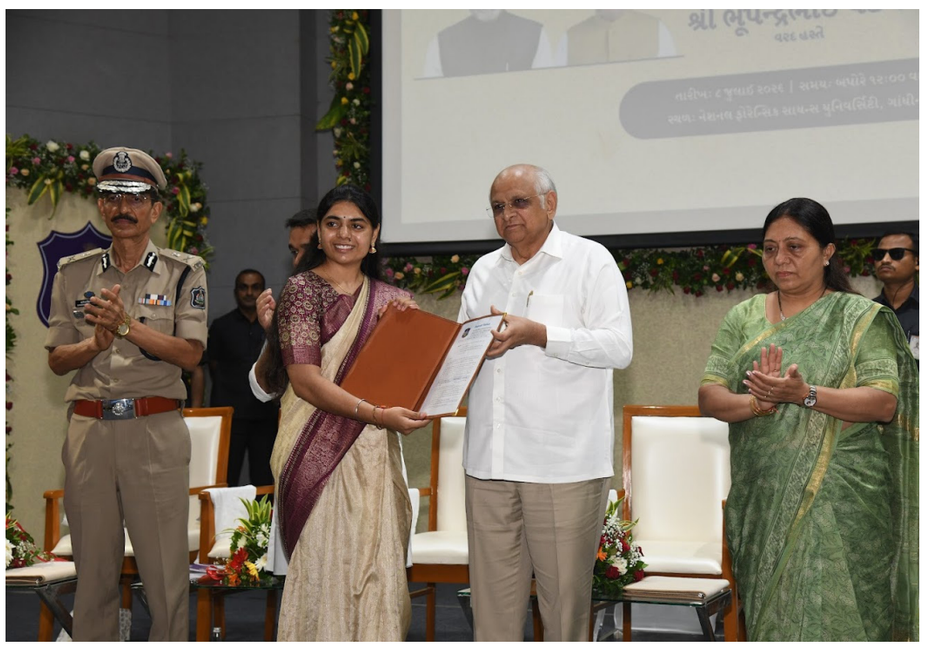

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात पुलिस में अशस्त्र पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) के रूप में शामिल हो रहे नवनियुक्त युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे निष्ठा, प्रामाणिकता और समाज सेवा की भावना के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए 'नागरिक देवो भव' एवं 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के मंत्र को साकार करें।

राज्य में कानून एवं व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 449 अशस्त्र पुलिस सब-इंस्पेक्टरों की नियुक्ति पुलिस बल में की गई है। बुधवार को इन नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का गरिमामय समारोह गांधीनगर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी विशेष रूप से उपस्थित रहे तथा उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों का उत्साहवर्धन किया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी राज्य का विकास शांति एवं सुरक्षा के बिना संभव नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि देश के रोल मॉडल के रूप में तथा व्यापार-उद्योग और वैश्विक निवेश के क्षेत्र में गुजरात ने जो ख्याति अर्जित की है, उसमें शांति और सुरक्षा के प्रहरी गुजरात पुलिस बल का महत्वपूर्ण योगदान है।

मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त युवा पुलिस सब-इंस्पेक्टरों को प्रेरित करते हुए कहा, "अब आप सभी इस पुलिस बल का हिस्सा बन चुके हैं। आपको ऐसा कार्य करना है कि समाज, आपके परिवार और पूरे राज्य को आप पर गौरव हो। राज्य और राष्ट्रहित की जिम्मेदारी का निर्वहन समाज के साथ मिलकर करना है।"

उन्होंने जोड़ा कि समाजिक जीवन में पुलिस का स्थान तथा सम्मान अत्यंत गौरवपूर्ण है। पुलिस की मात्र उपस्थिति से ही सामान्य नागरिक के मन में यह विश्वास पैदा होता है कि अब जो भी होगा, वह न्यायपूर्ण होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में किसी एक अधिकारी का उत्कृष्ट कार्य पूरे विभाग को क्रेडिट देने वाला बन जाता है। उन्होंने जोड़ा कि नवनियुक्त युवाओं को ऐसे कार्यों से प्रेरणा लेकर अच्छा सीखना चाहिए और पुलिस बल की छवि को और अधिक उज्ज्वल बनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि निष्ठा और प्रामाणिकता से कार्य करने वालों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रहती है। उन्होंने सभी से मिलकर गुजरात को शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में और अधिक मजबूत तथा गौरवशाली बनाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की सराहना की तथा नवनियुक्त युवाओं को अनुशासन का पालन करते हुए कर्तव्यनिष्ठ रहने की सीख भी दी।

उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात की यात्रा में पुलिस बल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि पुलिस बल में शामिल हुए ये नवनियुक्त युवा अपने लंबे सेवा-काल के दौरान वर्ष 2047 के विकसित भारत-विकसित गुजरात के निर्माण के वाहक बनेंगे।

गुजरात पुलिस परिवार के सदस्य बन रहे 449 नवनियुक्त अशस्त्र पुलिस सब-इंस्पेक्टरों का अभिनंदन करते हुए तथा उनका पुलिस परिवार में स्वागत करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि सामान्य जनता के लिए पुलिस का अर्थ अपराधियों को कानून के दायरे में लाने वाली एक फोर्स है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जब भी राज्य में कोरोना महामारी, भारी वर्षा जैसी प्राकृतिक आपदाएं अथवा कोई भी कठिन परिस्थिति आती है, तब जनता की सुरक्षा के लिए सबसे पहले पुलिस का ही नाम आता है।

उप मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून अपने हाथ में लेने वाले तत्वों को कानून का महत्व किस प्रकार समझाना है, यह आपको अवश्य आना चाहिए। और यदि आपमें से कोई स्वयं कानून अपने हाथ में लेगा, तो हमारे मृदुल तथा दृढ़ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की सरकार उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई करने में सक्षम है। सबसे अधिक भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करके प्रशासन को शुद्ध (गंगाजल पिलाने) करने का कार्य गुजरात के मुख्यमंत्री ने किया है।

आज के आधुनिक युग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में भी अपराधों की जांच में 'टेक्निकल इंटेलिजेंस' की अपेक्षा 'ह्यूमन इंटेलिजेंस' आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण पासा है।

गुजरात पुलिस के सुदृढ़ीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए उप ने कहा कि वर्ष 2033 तक सीधी भर्ती के माध्यम से कुल 50 हजार नई भर्तियां मुख्यमंत्री की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में पुलिस विभाग में कुल 54,509 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई है। इनमें से पिछले 5 वर्षों में ही 15,653 महिला कर्मियों की भर्ती कर महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2008 से अब तक लगभग 1 लाख युवा पुलिस विभाग में शामिल हो चुके हैं, जबकि वर्तमान में भी 13,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रगति पर है।

अहमदाबाद सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट केस में कल गुजरात हाईकोर्ट द्वारा सुनाए गए निर्णय का उल्लेख करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने कहा कि इस फैसले से यह स्पष्ट और दृढ़ संदेश गया है कि इस देश में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने इस समग्र देशद्रोह से जुड़े मामले की अत्यंत सूक्ष्म, वैज्ञानिक और पेशेवर ढंग से जांच करने वाली गुजरात पुलिस की जांच टीम को हृदयपूर्वक बधाई दी।

गृह विभाग के एक महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी देते हुए श्री संघवी ने कहा कि पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे राज्य के मध्यम एवं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब गुजरात के सभी जिला पुलिस मुख्यालयों के मैदान प्रतियोगी परीक्षाओं की शारीरिक परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए खोल दिए गए हैं, ताकि किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय अभ्यर्थी को निजी कोचिंग क्लासों पर अधिक खर्च न करना पड़े ।

इस अवसर पर राज्य पुलिस महानिदेशक श्री जी. एस. मलिक ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में गुजरात सरकार ने कानून एवं व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ करने के लिए पुलिस कॉन्स्टेबल से लेकर पीएसआई तक के विभिन्न संवर्गों में कुल 54,509 जवानों की पारदर्शी तथा सफल भर्ती पूर्ण की है। इसके अलावा; वर्ष 2026-27 में भी और 13,591 रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया बहुत ही तेजी से जारी है, जो राज्य सरकार की सुरक्षा के प्रति कटिबद्धता दर्शाती है।

श्री मलिक ने इस अवसर पर खाकी वर्दी धारण करने जा रहे 449 नवनियुक्त एवं उच्च शिक्षित पुलिस उप निरीक्षकों को अभिनंदन दिया और इस गौरवपूर्ण अवसर पर पीएसआई के साथ-साथ उनके परिवारों की भी इस सफलता के लिए प्रशंसा की तथा सभी नवनियुक्त अधिकारियों को निष्ठापूर्वक दायित्व निभाने के लिए शुभकामनाएं दीं।

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. नीरजा गोटरू के सक्षम नेतृत्व में हाल ही में हुई समग्र भर्ती प्रक्रिया काफी सुव्यवस्थित, न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई है। इस सफल एवं विवाद रहित कार्य के लिए डीजीपी ने डॉ. गोटरू को विशेष अभिनंदन दिया। श्री मलिक ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि पुलिस बल का हिस्सा बने नवनियुक्त पीएसआई अत्यंत टेक्नोसेवी तथा उच्च शिक्षित हैं। इन नवयुवाओं की देशभक्ति, अनुशासन और नैतिकता गुजरात पलिस की गरिमा को और ऊंचाई पर ले जाएगी।

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष डॉ. नीरजा गोटरू ने नवनियुक्ति पुलिस सब इंस्पेक्टरों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में यह भर्ती प्रक्रिया तेज तथा पारदर्शी ढंग से पूरी की गई है। मार्च-2024 में बोर्ड का गठन होने के बाद यह प्रथम सफल बैच है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 में घोषित की गई अशस्त्र पीएसआई की 472 रिक्तियों की भर्ती के लिए कुल 4.60 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। शारीरिक कसौटी, लिखित परीक्षा और विभिन्न दस्तावेज, मेडिकल आदि पारदर्शी प्रक्रिया पूरी कर यह चयन किया गया है। पुलिस कॉन्स्टेबल से पीएसआई होने के लिए मोड-2 विभागीय परीक्षा प्रक्रिया भी हाल में चल रही है। उन्होंने जोड़ा, "आप सभी नवनियुक्त अधिकारी आज जब अपने परिश्रम से गुजरात पुलिस में भर्ती हुए हैं, तब निष्ठा एवं प्रामाणिकता से नागरिकों की सेवा व सुरक्षा के लिए कार्यरत रहिएगा।"

इस अवसर पर मुख्यमंत्री व अन्य उपस्थित महानुभावों के करकमलों से फौजदारी कानूनों तथा प्रशिक्षण संबंधी पुस्तिकाओं का अनावरण किया गया। पुलिस विभाग द्वारा इन-हाउस बनाए गए ई-मॉड्यूल पहल का प्रारंभ भी किया गया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल तथा उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की गरिमामय उपस्थिति में गुजरात पुलिस अकादमी द्वारा तैयार की गई नई पुस्तकों का अनावरण किया गया। देश में लागू किए गए नए कानूनी प्रावधानों को समाविष्ट करने वाली इन नवप्रकाशित पुस्तकों में (1) भारतीय न्याय संहिता - 2023, (2) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता - 2023, (3) भारतीय साक्ष्य अधिनियम - 2023, (4) फोरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी व कम्युनिटी पुलिसिंग और (5) सेंट्रल तथा स्टेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, मानव व्यवहार तथा मानवाधिकार शामिल हैं। ये पुस्तकें आगामी समय में पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रशिक्षण तथा कानूनी समझ विकिसत करने में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगी।

समारोह में गांधीनगर की महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, अहमदाबाद के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) श्री गगनदीप गंभीर, गृह एवं पुलिस विभाग के उच्चाधिकारी और नवनियुक्त अशस्त्र पुलिस सब इंस्पेक्टर उपस्थित रहे।

पहली ही बारिश में डूब गए महानगर: गुरुग्राम से मुंबई तक हर साल क्यों दोहराती है शहरी तबाही, आखिर कब बदलेगी विकास की यह तस्वीर?

नई दिल्ली। मानसून भारत के लिए केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि जीवन, खेती और अर्थव्यवस्था की धुरी माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह मौसम देश के बड़े शहरों के लिए एक गंभीर परीक्षा बनता जा रहा है। जैसे ही तेज बारिश शुरू होती है, आधुनिक विकास, ऊंची इमारतों, एक्सप्रेस-वे और स्मार्ट सिटी के दावों के बीच शहरी व्यवस्था की कमजोरियां खुलकर सामने आ जाती हैं। इस वर्ष भी मानसून की पहली तेज बारिश ने गुरुग्राम, मुंबई, सूरत, पुणे, नासिक, कोल्हापुर और कई अन्य शहरों की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी। कहीं सड़कें नदियों में बदल गईं, कहीं वाहन घंटों जाम में फंसे रहे, कहीं पेड़ धराशायी हो गए तो कहीं इमारतें और दीवारें ढह गईं। हर साल अरबों रुपये की परियोजनाओं और विकास योजनाओं के बावजूद वही पुराने सवाल फिर खड़े हो गए हैं कि आखिर भारत के बड़े शहर हर मानसून में क्यों डूब जाते हैं और स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं निकल पाया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की तस्वीर सबसे पहले चर्चा में आई। मानसून की पहली तेज बारिश ने कुछ ही घंटों में पूरे शहर की रफ्तार थाम दी। राष्ट्रीय राजमार्ग-48 सहित प्रमुख सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। अनेक आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों में पानी इतना भर गया कि वाहन बीच सड़क पर बंद हो गए। कार्यालय जाने वाले लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे और आपातकालीन सेवाओं तक की आवाजाही प्रभावित हुई। हालात इतने गंभीर हो गए कि जिला प्रशासन और पुलिस को नागरिकों से अपील करनी पड़ी कि वे अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें और जहां संभव हो, 'वर्क फ्रॉम होम' करें। गुरुग्राम देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट और आईटी केंद्रों में गिना जाता है तथा हरियाणा के राजस्व में सबसे बड़ा योगदान देता है, लेकिन मानसून के दौरान यही शहर हर वर्ष जल निकासी व्यवस्था की कमजोरियों का प्रतीक बन जाता है।

गुजरात का औद्योगिक शहर सूरत भी इस बार रिकॉर्ड बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ। लगातार 36 घंटों में 11 से 19 इंच तक वर्षा दर्ज की गई, जिसने लगभग 85 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारी बारिश के कारण आवासीय कॉलोनियां, बाजार, व्यावसायिक परिसर और शॉपिंग मॉल तक पानी में डूब गए। कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई, पेड़ गिरने और बिजली गिरने जैसी घटनाओं में लोगों की जान गई तथा प्रशासन को बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। सूरत लंबे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। तेज शहरीकरण, नदी किनारे बढ़ते निर्माण और सीमित जल निकासी क्षमता के कारण हर मानसून में यही स्थिति दोहराई जाती है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भी इस बार लगातार हो रही बारिश और तेज समुद्री हवाओं के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। कुछ ही दिनों के भीतर शहर में एक हजार से अधिक पेड़ गिरने की घटनाएं दर्ज की गईं, जो पिछले कई वर्षों के पूरे मानसून के आंकड़ों से भी अधिक बताई जा रही हैं। कई लोगों की जान गई और अनेक घायल हुए। अंधेरी, माटुंगा, दादर, सायन और उपनगरों में पेड़ गिरने के कारण सड़कें बंद करनी पड़ीं। कई इलाकों में लोकल यातायात प्रभावित हुआ और निचले क्षेत्रों में जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। समुद्र में ऊंचे ज्वार और लगातार बारिश ने स्थिति को और जटिल बना दिया।

पेड़ गिरने की घटनाओं को लेकर अलग-अलग मत सामने आए हैं। महानगरपालिका का कहना है कि इस बार 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाओं ने बड़ी संख्या में पेड़ों को उखाड़ दिया। दूसरी ओर पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या केवल तेज हवा नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही गलत शहरी योजना है। शहरों में पेड़ों की जड़ों के आसपास कंक्रीट का अत्यधिक निर्माण, भूमिगत पाइपलाइन, पार्किंग, सड़क चौड़ीकरण और असंतुलित छंटाई के कारण पेड़ों की प्राकृतिक मजबूती कमजोर हो चुकी है। परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत कम तेज हवा में भी बड़े-बड़े पेड़ गिरने लगे हैं।

महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में भी मानसून ने व्यापक असर छोड़ा है। पुणे के खंडाला क्षेत्र में भूस्खलन की घटना में एक सुरक्षा गार्ड की मृत्यु हो गई। शहर में एक कचरा प्रबंधन केंद्र की इमारत ढहने से बचाव अभियान चलाना पड़ा। कोल्हापुर में नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई मंदिर और आसपास के क्षेत्र जलमग्न हो गए। नासिक में गोदावरी नदी खतरे के स्तर के करीब पहुंच गई और रामकुंड सहित कई धार्मिक स्थल पानी से घिर गए। अनेक जिलों में सड़क संपर्क प्रभावित हुआ तथा प्रशासन को राहत और बचाव दल तैनात करने पड़े। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पहले जहां लंबे समय तक मध्यम वर्षा होती थी, वहीं अब कम समय में अत्यधिक बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे क्लाउडबर्स्ट जैसे हालात शहरों की पुरानी ड्रेनेज प्रणाली के लिए बड़ी चुनौती बन रहे हैं। कई शहरों की जल निकासी व्यवस्था दशकों पहले की आबादी और निर्माण को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, जबकि आज जनसंख्या, कंक्रीट निर्माण और वाहनों की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है।

विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि शहरी बाढ़ केवल अधिक वर्षा का परिणाम नहीं होती। प्राकृतिक जलमार्गों पर अतिक्रमण, नालों का संकरा होना, जलाशयों का समाप्त होना, झीलों और तालाबों का भराव, अनियोजित कॉलोनियां, कंक्रीटीकरण और नियमित सफाई का अभाव इस संकट को कई गुना बढ़ा देता है। पहले जहां वर्षा का पानी जमीन में समा जाता था, वहीं अब अधिकांश सतह कंक्रीट से ढकी होने के कारण पूरा पानी सड़कों और नालों पर आ जाता है। यदि नाले प्लास्टिक, कचरे और गाद से भरे हों तो कुछ घंटों की तेज बारिश भी पूरे शहर को ठप कर सकती है।

शहरी नियोजन विशेषज्ञों का मानना है कि केवल नालों की सफाई या पंपिंग स्टेशन बढ़ा देने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। इसके लिए शहरों की पूरी जल निकासी प्रणाली का पुनर्निर्माण, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाना, प्राकृतिक जलमार्गों को पुनर्जीवित करना, निर्माण नियमों का सख्ती से पालन कराना और पर्यावरणीय दृष्टि से संतुलित विकास मॉडल अपनाना होगा। साथ ही नई कॉलोनियों और व्यावसायिक परियोजनाओं को मंजूरी देते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां वर्षा जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो।

जलवायु परिवर्तन ने इस चुनौती को और गंभीर बना दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में अत्यधिक वर्षा की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। ऐसे में यदि शहरों की आधारभूत संरचना को समय रहते मजबूत नहीं किया गया, तो हर मानसून के साथ आर्थिक नुकसान, जनहानि और अव्यवस्था का दायरा बढ़ता जाएगा। केवल राहत और बचाव अभियान पर्याप्त नहीं होंगे, बल्कि दीर्घकालिक शहरी सुधार योजनाओं को प्राथमिकता देनी होगी।

हर वर्ष मानसून के साथ वही तस्वीरें सामने आती हैं—जलमग्न सड़कें, घंटों लंबा ट्रैफिक जाम, बंद सार्वजनिक परिवहन, गिरते पेड़, ढहती इमारतें और परेशान नागरिक। यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि शहरी नियोजन, प्रशासनिक तैयारी और पर्यावरणीय संतुलन की संयुक्त परीक्षा है। यदि समय रहते व्यापक सुधार नहीं किए गए, तो गुरुग्राम, सूरत, मुंबई, पुणे और अन्य महानगरों में हर मानसून के साथ यही दृश्य दोहराते रहेंगे। देश के तेजी से विकसित होते शहरों को केवल आर्थिक विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के अनुकूल, सुरक्षित और टिकाऊ शहरी मॉडल के रूप में विकसित करना अब समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है।

27 साल पुराने नर्मदा भुगतान विवाद का ऐतिहासिक समाधानः सरदार सरोवर परियोजना पर चार राज्यों में बनी सहमति, जल, ऊर्जा और विकास को मिलेगी नई रफ्तार

नई दिल्ली। देश की सबसे महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं में शामिल सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े वर्षों पुराने वित्तीय और प्रशासनिक विवाद का आखिरकार समाधान हो गया है। केंद्र सरकार की पहल पर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच लंबे समय से लंबित नर्मदा अवॉर्ड भुगतान विवाद का ऐतिहासिक निपटारा हो गया। नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की उपस्थिति में चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते को सहकारी संघवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, क्योंकि इससे दशकों से चले आ रहे लागत साझाकरण और लंबित भुगतान के विवाद का स्थायी समाधान निकलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ केंद्र और चारों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। समझौते के तहत सरदार सरोवर परियोजना की निर्माण लागत से जुड़े लंबित देयों का एकमुश्त निपटान (वन-टाइम सेटलमेंट) करने पर सहमति बनी है, जिससे वर्षों से लंबित वित्तीय दायित्वों का समाधान किया जाएगा।

सरदार सरोवर परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, जलविद्युत उत्पादन और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को स्थायी जल उपलब्ध कराना है। इस परियोजना का लाभ गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र को अलग-अलग स्वरूप में मिलता है। हालांकि परियोजना के निर्माण, पुनर्वास और लागत साझाकरण से जुड़े भुगतान को लेकर लंबे समय से राज्यों के बीच मतभेद बने हुए थे। अब इस समझौते से इन विवादों का अंत होने की उम्मीद जताई जा रही है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि नर्मदा अवॉर्ड के लंबित भुगतान को लेकर चारों राज्यों के बीच वर्षों से विवाद चला आ रहा था, जिसका अब सौहार्दपूर्ण समाधान हो गया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारी संघवाद की भावना को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जल सुरक्षा, जल प्रबंधन और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं।

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों में बेहतर समन्वय स्थापित हुआ है, जिससे राजनीतिक मतभेद कम हुए हैं और राष्ट्रीय महत्व के कई लंबे समय से लंबित विवादों का समाधान संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि जब राज्य आपसी सहयोग और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उसका सबसे बड़ा लाभ देश के नागरिकों, विशेषकर किसानों को मिलता है।

उन्होंने चारों राज्यों की सरकारों की सराहना करते हुए कहा कि सरदार सरोवर जैसी विशाल अंतरराज्यीय परियोजना में सहमति बनाना आसान नहीं था, लेकिन सभी सरकारों ने रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया और राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दी। उनके अनुसार इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को मिला है, जहां सिंचाई क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ है, लाखों लोगों को पेयजल उपलब्ध हुआ है तथा जलविद्युत उत्पादन के माध्यम से ऊर्जा क्षमता में वृद्धि हुई है।

गृह मंत्री ने विशेष रूप से राजस्थान का उल्लेख करते हुए कहा कि पहली नजर में राज्य को मिलने वाला जल अपेक्षाकृत कम दिखाई दे सकता है, लेकिन जिन क्षेत्रों तक नर्मदा का पानी पहुंचा है वहां कृषि उत्पादन, भूमि की उत्पादकता और किसानों की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि रेगिस्तानी और जल संकट वाले क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने से खेती का स्वरूप बदला है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिली है।

महाराष्ट्र के लिए भी यह समझौता महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राज्य को परियोजना से सिंचाई, पेयजल और ऊर्जा के क्षेत्र में दीर्घकालिक लाभ मिलता है। साथ ही वित्तीय विवाद समाप्त होने से भविष्य की जल परियोजनाओं में समन्वय और निवेश की प्रक्रिया भी अधिक सरल हो सकेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि विवाद समाप्त होने से प्रशासनिक अनिश्चितता कम होगी और परियोजना से जुड़े शेष कार्यों को भी गति मिलेगी।

गुजरात इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य माना जाता है। सरदार सरोवर बांध के माध्यम से राज्य के अनेक सूखा प्रभावित जिलों तक नर्मदा का पानी पहुंचाया गया है। पेयजल आपूर्ति, सिंचाई और औद्योगिक विकास के लिए यह परियोजना राज्य की जीवनरेखा बन चुकी है। लाखों किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने से कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और कई क्षेत्रों में जल संकट काफी हद तक कम हुआ है।

मध्य प्रदेश को परियोजना से जलविद्युत उत्पादन और सिंचाई के क्षेत्र में व्यापक लाभ मिला है। राज्य के कई जिलों में कृषि विस्तार के साथ ग्रामीण विकास को भी नई गति मिली है। वहीं जलाशय और संबंधित परियोजनाओं ने क्षेत्रीय आधारभूत संरचना के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार जल विवादों को टकराव का विषय नहीं, बल्कि सहयोग और संवाद के माध्यम से हल करने में विश्वास रखती है। उन्होंने हाल ही में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल विवाद के समाधान तथा किशाऊ बांध परियोजना जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सभी सहकारी संघवाद के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनका कहना था कि किसी भी नदी का पानी किसी एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश की साझा प्राकृतिक संपदा है और उसका उपयोग अंततः देश के नागरिकों के हित में ही होता है।

उन्होंने राज्यों से अपील की कि जल विवादों का समाधान करते समय केवल क्षेत्रीय हित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि किसी पड़ोसी राज्य का विकास होता है, तो उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ अन्य राज्यों को भी मिलता है। इसलिए संवाद, सहयोग और पारदर्शिता के माध्यम से ऐसे विवादों को समय रहते सुलझाना आवश्यक है। जल विशेषज्ञों का मानना है कि सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े वित्तीय विवाद का समाधान केवल भुगतान का मामला नहीं है, बल्कि यह भविष्य में अंतरराज्यीय जल परियोजनाओं के लिए भी एक सकारात्मक संदेश है। देश में अनेक बड़ी नदी परियोजनाएं एक से अधिक राज्यों से जुड़ी हैं, जहां लागत, जल बंटवारा और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर समय-समय पर मतभेद उत्पन्न होते रहे हैं। ऐसे में यह समझौता भविष्य के लिए एक व्यावहारिक मॉडल साबित हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार जलवायु परिवर्तन, बढ़ती आबादी और जल संसाधनों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए राज्यों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। यदि इसी प्रकार संवाद और सहमति के माध्यम से विवादों का समाधान होता रहा, तो देश में जल सुरक्षा, सिंचाई विस्तार, पेयजल उपलब्धता और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में दीर्घकालिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। सरदार सरोवर परियोजना पर हुआ यह ऐतिहासिक समझौता केवल चार राज्यों के बीच वित्तीय विवाद का अंत नहीं, बल्कि सहकारी संघवाद, साझा विकास और राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राज्य पुलिस महानिदेशक श्री जी. एस. मलिक, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त श्री अनुपम सिंह गहलोत तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की

▸▸ उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी ने रथयात्रा से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था एवं तैयारियों की समीक्षा की

▸▸ उप मुख्यमंत्री ने रथयात्रा से पहले की सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति तथा विभिन्न विभागों की पूर्व तैयारियों की समीक्षा की

गांधीनगर : अहमदाबाद में आगामी आषाढ़ी दूज के दिन आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथजी की 149वीं रथयात्रा शांतिपूर्ण रूप से सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो; इस उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी की अध्यक्षता में बुधवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री ने रथयात्रा से पूर्व की सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं, कानून एवं व्यवस्था की स्थिति तथा विभिन्न विभागों की पूर्व तैयारियों की सूक्ष्मतापूर्वक समीक्षा की। उन्होंने रथयात्रा के दौरान समग्र शहर में शांति तथा सुरक्षा बनी रहे; इसके लिए पुलिस प्रशासन का पूरी तरह सज्ज रहने का आह्वान किया था।

उन्होंने रथयात्रा के रूट पर कड़ा पुलिस प्रबंध करने, यातायात का सुचारु संचालन करने तथा इमर्जेंसी सेवाओं को सुदृढ़ करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं सुझाव दिए।

उप मुख्यमंत्री ने बैठक में रथयात्रा बंदोबस्त के आयोजन को लेकर विस्तृत चर्चा की, जिसमें अधिकारियों द्वारा रूट के संवेदनशील पॉइंट्स का दौरा, स्थानीय अग्रणियों के साथ संवाद और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया गया।

उप मुख्यमंत्री ने टेक्नोलॉजी तथा मानव बल के उत्कृष्ट समन्वय से सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने पर बल दिया। रथयात्रा पूर्ण आस्था एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में निर्विघ्न संपन्न हो; इसके लिए सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने का उप मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था।

उल्लेखनीय है कि इस वर्ष रथयात्रा में सुरक्षा प्रणाली को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी आधारित अनेक नई परियोजनाएँ लागू की गई हैं। इनमें रथयात्रा के इतिहास में पहली बार रूट पर शामिल होने वाले हाथियों की सुरक्षा तथा लाइव लोकेशन मॉनिटरिंग के लिए 'गजरक्षक स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम' कार्यरत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त; यात्रा में शामिल होने वाले सभी ट्रकों तथा अखाड़ों के संचालकों के आधार कार्ड आधारित वेरीफिकेशन के लिए 'प्रतिरक्षा' एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा और संदिग्ध तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए 'पिनैक' सॉफ्टवेयर संचालित एआई फेस रिकग्निशन सिस्टम, हवाई सुरक्षा के लिए एंटी-ड्रोन गन तथा जैमर टीम तथा समग्र रूट पर हजारों सीसीटीवी कैमरा के नेटवर्क द्वारा लाइव सर्वेलांस की आधुनिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री संजीव कुमार, राज्य पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) श्री जी. एस. मलिक, अहमदाबाद पुलिस आयुक्त श्री अनुपम सिंह गहलोत, महानगर पालिका आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि, अहमदाबाद जिला कलेक्टर श्री भव्य वर्मा सहित पुलिस विभाग के उच्च पदाधिकारी तथा विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी विशेष रूप से उपस्थित रहे और उन्होंने रथयात्रा सुरक्षा के लिए व्यापक एक्शन प्लान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

550 वर्ष पुरानी हवेली संगीत परंपरा को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान

उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार-2025 के लिए हवेली संगीत के विद्वान आचार्य श्री रणछोडलालजी गोस्वामी का चयन

गांधीनगर : भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीन एवं समृद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले पुष्टिमार्गीय हवेली संगीत को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगीत नाटक अकादमी द्वारा वर्ष 2024 -25 के लिए घोषित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार- 2025 के लिए अहमदाबाद के कालुपुर स्थित गोस्वामी हवेली की 16वीं पीढ़ी के आचार्य तथा हवेली संगीत के विद्वान आचार्य श्री रणछोडलालजी गोस्वामी का चयन किया गया है।

आचार्य रणछोडलालजी गोस्वामी इस सम्मान को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि से अधिक संपूर्ण हवेली संगीत परंपरा का गौरव मानते हैं। वे कहते हैं, "यह पुरस्कार भारत की भक्ति, संगीत और संस्कृति की समृद्ध परंपरा को मिला सम्मान है। हवेली संगीत में भारत की आत्मा बसती है।"

पुष्टिमार्ग की स्थापना महाप्रभु श्री वल्लभाचार्यजी ने लगभग 550 वर्ष पहले की थी। इस परंपरा में कीर्तन

और संगीत को भक्ति का सर्वोच्च साधन माना जाता है। आज भी हवेलियों में दिन के विभिन्न प्रहरों तथा ऋतुओं के अनुरूप विशिष्ट रागों में सेवा-कीर्तन किया जाता है। वसंत, ग्रीष्म, श्रावण अथवा शरद; प्रत्येक ऋतु के लिए अलग संगीत परंपरा विकसित की गई है, जो हवेली संगीत को विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। अहमदाबाद के 450 वर्ष पुराने दोषीवाडा की पोल स्थित गोस्वामी हवेली के आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित रणछोडलालजी गोस्वामी ने गुरु-शिष्य परंपरा में संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। साथ ही उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के उपासना स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स से संगीत विषय में स्नातकोत्तर एवं एमफिल पूर्ण किया है तथा वर्तमान में पीएचडी शोधकार्य कर रहे हैं। मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने 22 हजार से अधिक भक्तिपदों की रचना की है तथा आठ पुस्तकों का सृजन किया है। वे गुजरात यूनिवर्सिटी के हवेली संगीत पाठ्यक्रम में विशेषज्ञ के रूप में भी सेवाएं दे रहे हैं। व्रजभाषा, गुजराती, संस्कृत के अतिरिक्त चारणी, मेवाड़ी और मारवाड़ी जैसी भाषाओं में भी उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं।

आचार्य के अनुसार हवेली संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल स्वरूप है। प्रबंध, ध्रुपद और धमार जैसी प्राचीन गायन परंपराओं से ही आगे चलकर खयाल गायकी का विकास हुआ है। हवेली संगीत में आज भी ये मूल परंपराएं जीवंत हैं।

वे कहते हैं कि महाप्रभु श्री वल्लभाचार्यजी तथा श्री विट्ठलनाथजी के समय से सूरदास, परमानंददास सहित अष्टछाप के कवियों की रचनाएं हवेली संगीत के माध्यम से गाई जाती रही हैं। यह संगीत केवल कला का स्वरूप नहीं, बल्कि भक्ति और उपासना का जीवंत माध्यम है। आचार्य का मानना है कि यह पुरस्कार संपूर्ण वैष्णव समाज तथा शास्त्रीय संगीत प्रेमियों के लिए गौरव का क्षण है। गुजरात और राजस्थान के अलावा मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा पंजाब में भी यह परंपरा आज जीवंत है। स्वतंत्रता के बाद हवेली संगीत को इतने उच्च राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त होने की यह संभवतः पहली घटना है।

हवेली संगीत के संरक्षण के संबंध में वे सुझाव देते हैं कि यूनिवर्सिटी स्तर पर पूर्णकालिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जाने चाहिए। आधिकारिक ग्रंथों का सृजन, अनुसंधान, दस्तावेजीकरण तथा तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। साथ ही युवा पीढ़ी में इस परंपरा के प्रति रुचि जागृत हो, इसके लिए सेमिनार, कार्यशालाओं तथा व्याख्यानमालाओं का आयोजन भी समय की आवश्यकता है।

पांच शताब्दियों से अधिक समय से मंदिरों की दीवारों में गूंजता हवेली संगीत का स्वर अब राष्ट्रीय मंच तक पहुंच चुका है। यह सम्मान केवल एक कलाकार का नहीं, बल्कि भारत की अमूल्य संगीत विरासत का गौरव बढ़ाने वाला एक मील का पत्थर बन गया है।

अहमदाबाद मंडल ने जून-2026 में वाणिज्यिक क्षेत्र में रचा नया कीर्तिमान,606.43 करोड़ का सर्वाधिक मासिक माल राजस्व, 767.01 करोड़ का सकल राजस्व

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने जून-2026 के दौरान मण्डल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश के नेतृत्व में वाणिज्यिक क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हुए माल राजस्व, पार्सल व्यवसाय, गैर-किराया राजस्व, यात्री सुविधाओं तथा टिकट जांच अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। मंडल ने विभिन्न क्षेत्रों में कई नए कीर्तिमान स्थापित किए।

माल राजस्व (Freight Business)

▸▸ जून-2026 में 606.43 करोड़ का माल राजस्व अर्जित किया गया, जो निर्धारित लक्ष्य से 3.60% तथा गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में 13.59% अधिक है। यह वित्तीय वर्ष 2026-27 का अब तक का सर्वाधिक मासिक माल राजस्व है।

▸▸ 30 जून 2026 को 26.58 करोड़ का एक दिवसीय माल राजस्व अर्जित कर नया रिकॉर्ड स्थापित किया गया।

पार्सल व्यवसाय (Parcel Business)

▸▸ जून-2026 में 6.19 करोड़ का पार्सल राजस्व अर्जित किया गया, जो गत वर्ष की तुलना में 7.65% अधिक है।

▸▸ भुज से बांद्रा टर्मिनस तक 22 टन आम पार्सल सेवा के माध्यम से भेजा गया, जिससे एक ही दिन में 1.26 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

यात्री व्यवसाय एवं कोचिंग (Passenger Business & Coaching)

▸▸ जून-2026 में 145.58 करोड़ का यात्री राजस्व अर्जित किया गया।

▸▸ अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के लिए 67 विशेष रेल सेवाएं संचालित की गईं।

▸▸ यात्रियों की सुविधा के लिए 122 अतिरिक्त कोच लगाए गए, जिससे लगभग 0.97 लाख यात्रियों को लाभ मिला तथा 10.33 करोड़ का अतिरिक्त यात्री राजस्व अर्जित हुआ।

टिकट जांच एवं स्वच्छता अभियान (Ticket Checking & Cleanliness Drive)

▸▸ जून-2026 में टिकट जांच के माध्यम से 2.70 करोड़ की आय अर्जित की गई, जो गत वर्ष की तुलना में 23.29% अधिक है।

▸▸ स्वच्छता अभियान के अंतर्गत 1,230 एंटी-लिटरिंग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2.20 लाख का जुर्माना वसूला गया।

गैर-किराया राजस्व (Non-Fare Revenue) – नई पहल

▸▸ कांकारिया गुड्स शेड में एक्सेस-कंट्रोल्ड पेड पार्किंग एवं फ्रेट एलाइड सर्विसेज के लिए 7 वर्ष की अवधि का 20.73 करोड़ मूल्य का अनुबंध प्रदान किया गया।

▸▸ सभी गैर-प्रीमियम ट्रेनों में ट्रेन साइड वेंडिंग (TSV) के लिए 3 वर्ष की अवधि का 3.71 करोड़ मूल्य का अनुबंध प्रदान किया गया।

▸▸ ट्रेन संख्या 22961/22962 में हेडरेस्ट कवर पर विज्ञापन के माध्यम से 0.57 करोड़ का संविदात्मक राजस्व प्राप्त हुआ।

▸▸ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आधुनिक डिजिटल लगेज लॉकर सुविधा प्रारंभ की गई, जिससे यात्रियों को सुरक्षित एवं स्वचालित सामान भंडारण की सुविधा उपलब्ध हुई।

यात्री सुविधाएं (Passenger Amenities)

▸▸ ग्रीष्मकाल के दौरान विभिन्न स्टेशनों पर स्टेशन कर्मचारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए शीतल पेयजल की समुचित व्यवस्था की गई।

विकास भी, विरासत भी : श्री कृष्ण-रुक्मिणी यात्राधाम सज रहा है नए श्रृंगार 43.72 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे चरण के विकास कार्यों का शुभारंभ

▸▸ दूसरे चरण में माधवरायजी मंदिर के पुनरुद्धार सहित अनेक विकास कार्यों का समावेश

▸▸ भव्य बीच फ्रंट, आधुनिक फूड कोर्ट, विशाल आउटर प्लाजा और पार्किंग का निर्माण होगा

▸▸ श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए सड़कें होंगी चौड़ी, मंदिर तक बनेगी एप्रोच रोड

▸▸ अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम से सज्ज बनेगा समग्र परिसर

गांधीनगर, 08 जुलाई : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी, विरासत भी' के मंत्र को चरितार्थ करते हुए आज मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में राज्य का धार्मिक पर्यटन एक स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रहा है। 'विकास भी, विरासत भी' का जीवंत उदाहरण बन रहा है पोरबंदर जिले का माधवपुर स्थित 'श्री कृष्ण-रुक्मिणी यात्राधाम', जहाँ भगवान श्री कृष्ण तथा माता रुक्मिणी का विवाह हुआ था। इस प्रागैतिहासिक एवं आध्यात्मिक स्थल को अब वैश्विक पटल पर जगमगाने योग्य बनाने के लिए गुजरात सरकार तथा उसके उपक्रम गुजरात पवित्र यात्राधाम विकास बोर्ड द्वारा महत्वाकांक्षी मास्टर प्लानिंग पर कार्य चल रहा है।

संपूर्ण प्रोजेक्ट अंतर्गत माधवपुर गाँव में एक-एक किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी पौराणिक स्थलों को एक सुंदर सूत्र में पिरोया जा रहा है। प्रथम चरण में 47.99 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मजबूत आधार पर आगे बढ़ते हुए दूसरे चरण के कार्य शुरू करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। प्रथम चरण में श्री रुक्मिणी माताजी मंदिर, विवाह वेदी की साक्षी 'चोरी मायरा', पवित्र ब्रह्मकुंड तथा भव्य मुख्य प्रवेश द्वार का सफल लोकार्पण स्वयं मुख्यमंत्री द्वारा हो जा चुका है। अब दूसरे चरण का कार्य पूर्ण गति के साथ शुरू हो गया है। राज्य सरकार द्वारा 43.72 करोड़ रुपए की लागत से दूसरे चरण के विकास कार्यों को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। दूसरा चरण दो वर्षों के भीतर पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

भव्य कायाकल्प : 20.25 करोड़ रुपए से सुसज्जित होगा ऐतिहासिक माधवरायजी मंदिर का स्वरूप

दूसरे चरण का सबसे महत्वपूर्ण भाग भगवान माधवरायजी के मंदिर का जीर्णोद्धार करना है। 20.25 करोड़ रुपए की लागत से इस ऐतिहासिक मंदिर को नया स्वरूप दिया जाएगा। यह कार्य पूर्ण होने पर यहाँ अध्यात्म, इतिहास और प्राचीन स्थापत्य कला का अद्वितीय संगम देखने को मिलेगा।

समुद्र तट पर पर्यटन का नया रोमांच : 200 मीटर लंबा भव्य बीच फ्रंट तथा आधुनिक फूड कोर्ट तैयार होंगे

माधवरायजी मंदिर के निकट स्थित समुद्र तट को नए पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ कुल 200 मीटर लंबे क्षेत्र में बीच डेवलपमेंट किया जाएगा। पर्यटकों की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर आधुनिक फूड कियोस्क, हाईटेक शौचालय तथा बैठकों की अत्यंत सुंदर व्यवस्था (फूड कोर्ट सिटिंग) तैयार की जा रही है।

श्रद्धालुओं को ट्रैफिक जाम से मुक्ति : 5.31 करोड़ रुपए की लागत से बनेंगे विशाल आउटर प्लाजा एवं पार्किंग

माधवपुर मेले तथा त्योहारों के दौरान उमड़ने वाली भारी भीड़ के सुगम प्रबंधन के लिए मंदिर परिसर के बाहरी भाग का सुव्यवस्थित विकास किया जा रहा है। 5.31 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह विशाल आउटर प्लाजा तथा व्यवस्थित पार्किंग स्थल श्रद्धालुओं की आवाजाही को अत्यंत सरल एवं सुरक्षित बनाएंगे।

चौड़ी सड़कों से आसान बनेगा मार्ग : काचबा उछेर केन्द्र से मंदिर तक बनेगी 9 मीटर चौड़ी एप्रोच रोड

कनेक्टिविटी को नया विस्तार देने के लिए सड़क एवं भवन विभाग के नेतृत्व में महत्वपूर्ण आधारभूत कार्य शुरू हुए हैं। इसके अंतर्गत स्थानीय काचबा उछेर केन्द्र (कछुआ पालन केन्द्र) से सीधे माधवरायजी मंदिर तक पहुँचने वाले मार्ग को 9 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है, जिससे सँकरी सड़कों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।

सेल्फी पॉइंट्स एवं कलात्मक मूर्तियाँ : 3.45 करोड़ रुपए से 'इंस्टाग्राम फ्रेंडली' बनेगा रुक्मिणी-कृष्ण धाम

युवा पीढ़ी तथा आधुनिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस धार्मिक परिसर को नया लुक दिया जा रहा है। 3.45 करोड़ रुपए के बजट से समग्र क्षेत्र में भव्य लैंडस्केप, रंग-बिरंगे फाउंटेन, सनातन संस्कृति को दर्शाने वाली विभिन्न कलात्मक मूर्तियाँ (स्कल्पचर्स), स्पष्ट साइन बोर्ड और आकर्षक सेल्फी पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं।

अत्याधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर : अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग और स्मार्ट इरीगेशन सिस्टम से सज्ज बनेगा समग्र परिसर

परिसर की सुंदरता में कोई अवरोध न आए; इसके लिए सभी मूलभूत लाइनों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। समग्र प्रोजेक्ट क्षेत्र में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल, प्लंबिंग तथा पेड़ों, पौधों एवं लैंडस्केप की हरियाली सदाबहार बनी रहे; इसके लिए आधुनिक इरीगेशन (सिंचाई) सिस्टम का नेटवर्क बिछाया जा रहा है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विज़न को साकार करने वाला माधवपुर का यह नया एवं भव्य स्वरूप करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को नई शक्ति प्रदान करेगा और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार तथा आर्थिक समृद्धि के नए द्वार भी खोलेगा।

अहमदाबाद मंडल ने मानसून के दौरान सुरक्षित रेल परिचालन के लिए तैयारियों की समीक्षा की,यात्री सुरक्षा एवं निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियों पर जोर

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में मानसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा रेल परिचालन को सुरक्षित एवं सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से मंडल रेल प्रबंधक (DRM) अहमदाबाद, श्री वेद प्रकाश की अध्यक्षता में मंडल कार्यालय में मानसून तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य (इन्फ्रास्ट्रक्चर) श्री अनिल कुमार खंडेलवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों तथा मानसून प्रबंधन से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों और मण्डल के सभी सीनियर सेक्शन इंजीनियर्स (वर्क्स) ने (वर्चुअल माध्यम) से भाग लिया। मानसून के दौरान संभावित चुनौतियों से निपटने हेतु की गई तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई।

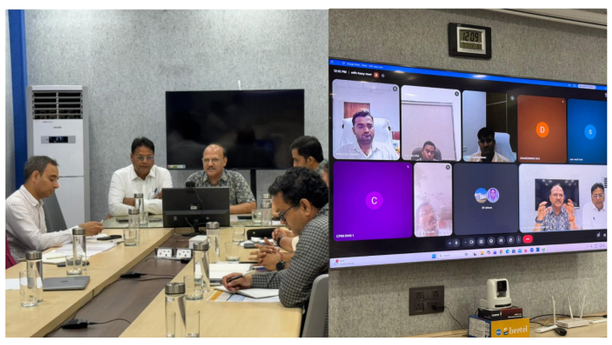

यात्री सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता

मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने कहा कि अहमदाबाद मंडल ने मानसून के दौरान सुरक्षित और निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। मानसून से पहले ट्रैक, पुलों, ड्रेनों और कलवर्टों का निरीक्षण एवं सफाई की जाती है। राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ संयुक्त सर्वे कर संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की जाती है और जल निकासी सुनिश्चित की जाती है।

स्टेशनों और यार्डों में जलभराव रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। संभावित जोखिम वाले पुलों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और आवश्यकता पड़ने पर कॉशन ऑर्डर जारी किए जाते हैं। स्टेशन शेड, छतों और उपकरणों की भी जांच की जाती है।

मानसून के दौरान सुरक्षित एवं निर्बाध रेल संचालन सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद मंडल द्वारा व्यापक स्तर पर विशेष तैयारियां की गई हैं जैसेः-

जल निकासी व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 132 किलोमीटर साइड ड्रेनों की सफाई की गई तथा 190 स्थानों पर पेड़ों की कटाई एवं ट्रिमिंग का कार्य किया गया।

जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए आरयूबी (RUB) स्थलों पर 10 एवं 32 एचपी क्षमता के कुल 260 पंप लगाए गए हैं।

ट्रैक एवं यार्ड में जल निकासी बेहतर बनाए रखने के लिए 675 किलोमीटर क्षेत्र में फ्लैंज क्लीयरेंस का कार्य किया गया तथा 37 सम्प (Sumps) स्थापित किए गए हैं।

आपात स्थिति से निपटने के लिए धांगध्रा, गांधीधाम, मालिया और आदरज मोटी में बैलेस्ट और क्वारी डस्ट का पर्याप्त भंडारण किया गया है तथा विशेष आपातकालीन गैंग तैयार रखे गए हैं।

आपदा प्रबंधन एवं त्वरित बहाली की व्यवस्था

बाढ़ अथवा अन्य प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में रेल सेवाओं की शीघ्र बहाली के लिए आवश्यक सामग्री पहले से ही रणनीतिक स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है।

धांगध्रा में 7 वैगन बैलेस्ट एवं 7 वैगन क्वारी डस्ट की व्यवस्था की गई है।

गांधीधाम में 20 वैगन बैलेस्ट तथा 10 वैगन क्वारी डस्ट उपलब्ध रखी गई है।

मालिया एवं आदरज मोटी में 10,000-10,000 घनमीटर बैलेस्ट का रिजर्व स्टॉक सुरक्षित रखा गया है।

मानसून तैयारियों के मुख्य बिंदु

बैठक में मानसून तैयारियों के अंतर्गत जल निकासी व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जलभराव की स्थिति से बचने के लिए साइड ड्रेन, कैच वाटर ड्रेन, क्रॉस ड्रेन तथा स्टेशन यार्ड ड्रेनों की नियमित एवं व्यवस्थित सफाई सुनिश्चित की जाए। यह व्यवस्था ट्रैक की स्थिरता बनाए रखने तथा सिग्नलिंग प्रणाली की विश्वसनीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

संवेदनशील स्थलों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी एवं गुणवत्तापूर्ण निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों को समय रहते मजबूत किया जा सके। साथ ही रेलवे यार्डों में सिग्नल फेल्योर जैसी परिस्थितियों से बचाव के लिए इंजीनियरिंग, सिग्नल एवं दूरसंचार, विद्युत तथा परिचालन सहित विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया।

बैठक में रेलवे को प्रभावित करने वाले जलाशयों (Railway Affecting Tanks – RAT) की सतत निगरानी के लिए स्थानीय प्रशासन एवं ग्राम प्रधानों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखने का निर्णय लिया गया, जिससे संभावित जोखिमों की समय रहते जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संवेदनशील स्थानों पर मानसून रिजर्व सामग्री तथा आपातकालीन बहाली उपकरण (Emergency Restoration Equipment) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। अहमदाबाद मंडल मानसून के दौरान यात्रियों की सुरक्षा, संरक्षित रेल परिसंपत्तियों तथा निर्बाध रेल परिचालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।